CMYK CMYK

12 सितंबर को उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे सीपी राधाकृष्णन

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

सियाचिन बेस कैंप पर भीषण हिमस्खलन, 3 जवान शहीद; 5 जवानों के अभी भी बर्फ में फंसे होने की खबर

RNI Regn. No.7789/1964 वर्ष-61 > अंक - 256 रायपुर गुरूवार 11 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082 पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया 'बहुत अच्छा दोस्त', ट्रेड वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा

प्रधानमंत्री ने दिया जवाब

नई दिल्ली/वाशिंगटन एजेंसी।

भारत के साथ रिश्तों में तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 'बहुत अच्छा दोस्त' भी बताया और कहा कि वह 'आने वाले हफ्तों में' उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ट्रंप का यह ताजा बयान अमेरिका की ओर से हाल ही में आई नरमी के बाद आया है।

प्रधानमंत्री ने ट्रंप के पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और नेचुरल पार्टनर्स हैं। मुझे भरोसा है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत-अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं का रास्ता प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रंप ने कहा, 'मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त रहूंगा' और ट्रंप ने उन्हें 'महान प्रधानमंत्री' भी बताया।

पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अक्टूबर से शुरू होगा

चुनाव आयोग का फैसला

नईदिल्ली एजेंसी

बिहार की तरह पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अक्टूबर से शुरू हो सकता है। चुनाव आयोग ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ की बैठक में इस प्रक्रिया की तैयारियों पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने सभी सीईओ से 30 सितंबर से पहले संशोधन से जुड़ी सभी जरूरी कार्यवाही को पूरा करने को कहा है, ताकि इसकी घोषणा की जा सके। बताया जा रहा है कि बिहार के चुनाव समाप्त होने से पहले ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो सकती है। सीईओ के द्वारा प्रगति रिपोर्ट सौंपने के बाद चुनाव आयोग एसआईआर का ऐलान कर देगा। इसमें मतदाता सूची अपडेट किए जाने का काम शुरू होगा। एसआईआर एक तरह से नई मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें काफी गहन तरीके से मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा की जाती है।

बिहार को मोदी कैबिनेट की 7500 करोड़ की सौगात, वैष्णव बोले- विकास को मिली गति

दक्षिण बिहार को कोलकाता से जोड़ने वाली परियोजना को केंद्र की मंजूरी

नईदिल्ली,एजेंसी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में 7,500 करोड़ की एक रेलवे और एक राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने कहा कि देश में बुनियादी ढाँचे के निर्माण की गति बेहतर हुई है।

बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान वैष्णव ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वैष्णव ने आगे कहा कि बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के 4-लेन ग्रीनफ़ील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड मोकामा-मुंगेर सेक्शन के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,169 करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इन परियोजनाओं की जानकारी दी।

बिहार की होगी आर्थिक प्रगति

सरकार का मानना है कि यह हाई-स्पीड कॉरिडोर बिहार की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा. सड़क अवसंरचना के विस्तार से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि कृषि और स्थानीय उद्योगों को भी राष्ट्रीय बाज़ारों तक आसानी से पहुंचने का मौका मिलेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि हाई-स्पीड सड़क परियोजनाएं बिहार जैसे राज्य में विकास का आधार तैयार करती हैं. बेहतर कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों में भी सुधार होगा. इस कदम से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.

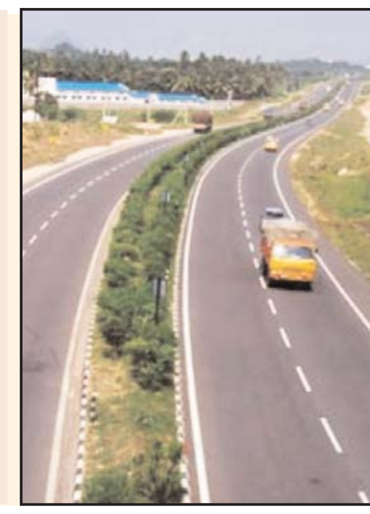

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन (177 किलोमीटर) के दोहरीकरण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 3,169 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 3169 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली एक अहम परियोजना भी है। अगर हम इस परियोजना को नक्शे में देखें तो यह बिहार से शुरू होकर रामपुरहाट में झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है।

इस परियोजना की बदौलत सफर होगा आसान बकौल वैष्णव, इस परियोजना की बदौलत दक्षिण बिहार की कोलकाता से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें भागलपुर से मालदा टाउन और रामपुरहाट होते हुए हावड़ा जाती हैं, लेकिन इस दोहरीकरण के बाद, कई ट्रेनें भागलपुर से दुमका और वहां से सीधे रामपुरहाट जा सकेंगी। कई पैसेंजर ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस भी इससे होकर गुजर सकेंगे और वह देवघर तीर्थस्थल को भी जोड़ती है। एक तरह से दक्षिण बिहार को कोलकाता से जिस कनेक्टिविटी की जरूरत है, वह इस परियोजना से पूरी हो जाती है।

जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ नेपाली नागरिक गिरफ्तार, पाक से ऑपरेट हो रहे थे भारतीय सिम

एजेंसी

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय जासूसी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए नेपाल के नागरिक प्रभात कुमार चौरसिया (43 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने और भारत की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने नाम पर भारतीय मोबाइल सेवा प्रदाताओं (एयरटेल और जियो) से 16 सिम कार्ड प्राप्त किए थे। इन सिम कार्ड्स में से 11 का इस्तेमाल पाकिस्तान के शहरों-लाहौर, बहावलपुर आदि-में व्हाट्सऐप के जरिए किया जा रहा था। सिम कार्ड नेपाल के रास्ते आईएसआई एजेंटों तक पहुंचाए गए। स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक, इन व्हाट्सऐप नंबरों का इस्तेमाल भारतीय सेना के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने और रक्षा-संबंधी जानकारियाँ एकत्र करने की कोशिशों में किया जा रहा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि चौरसिया वर्ष 2024 से आईएसआई के संपर्क में था और उसे अमेरिका का वीजा तथा पत्रकारिता करियर के नाम पर लालच दिया गया था। आरोपी के खिलाफ दिल्ली के PS Special Cell थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2)/152 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक : सीएम योगी

गोरखपुर एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि गरीबों की जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल कब्जामुक्त कराने के साथ दबंगों को कानूनी सबक सिखाया जाए। किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले और कमजोरों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ विधि सम्मत कड़ा एक्शन लिया जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे।

मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक-

एक करके सबकी समस्याएं सुनीं।

उन्होंने इस दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात कर सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जनता दर्शन में एक महिला ने दबंगों द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जा की शिकायत पर त्वरित एक्शन लिया जाए। जमीन कब्जामुक्त होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।

आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी किया गिरफ्तार

रांची एजेंसी।,दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में बुधवार को रांची के लोअर बाजार इलाके से आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को गिरफ्तार किया गया। उसने शहर के इस्लामनगर स्थित तबारक लॉज को ठिकाना बना रखा था। उसके पास से हथियार, केमिकल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और एटीएस ने झारखंड के पलामू में भी छापेमारी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आतंकी अशहर दानिश मूल रूप से झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफी समय से उसकी तलाश में थी। उसके खिलाफ दिल्ली में दर्ज एक मामले के आधार पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी।

भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, हिंसक प्रदर्शन के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

एजेंसी

नई दिल्ली नेपाल में पिछले दो दिनों से हो रहे हिंसक प्रदर्शन के चलते केंद्रीय एजेंसियों ने भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। आगाह किया गया है कि उपद्रवी तत्व इस अशांति का फायदा उठाकर पड़ोसी भारतीय राज्यों में हिंसा भड़का सकते हैं। खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है कि नेपाल के अशांत माहौल का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व सीमावर्ती भारतीय राज्यों में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते

हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस खुफिया जानकारी के बाद उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सहित भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर कानून-व्यवस्था के किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और सख्त कर दिया गया है।

विश्व | **फ्रांस में सरकार विरोधी प्रदर्शन: लाखों लोग सड़कों पर, कई जगह आगजनी, 200 से ज्यादा गिरफ्तार**

नेपाल की राह पर फ्रांस, सुलग उठी हिंसक आग, लोग मांग रहे मैक्रों का इस्तीफा

पेरिस, एजेंसी

नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने सड़कें जाम कर दीं, कूड़ेदान में आग लगाई और कई जगहों पर पुलिस से भी भिड़ गए। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त हो रहे हैं, जब मैक्रों ने बीते दिन ही सेबेस्टियन लेकोर्नू को नया प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के लगभग हर बड़े शहर में लोग सड़कों पर हैं। 50 नकाबपोश लोगों ने बोर्डो में सड़कें जाम कर दीं और टूलूज में रेलवे लाइन पर तोड़फोड़ की। मार्सिले, मोंटपेलियर, नैनटेस

और ल्योन सहित पूरे फ्रांस में हाईवे पर जाम की खबरें हैं।

आंतरिक मंत्री ब्रूनो रिटेलेउ ने कहा कि पश्चिमी शहर रेनेस में एक बस में आग लगा दी गई और एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचाने से ट्रेनें अवरुद्ध हो गईं।

गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने बताया कि पुलिस रातभर से गिरफ्तारियां कर रही हैं। करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिटेलो ने कहा कि पूरे देश में 80,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जिनमें से 6,000 पेरिस में हैं। पेरिस पुलिस ने बताया कि अब तक प्रदर्शनों में 132 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नैनटेस शहर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। मोंटपेलियर में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई।

इन प्रदर्शनों को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है, जिसका नेतृत्व एक वामपंथी समूह कर रहा है। हालांकि, आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। इसकी नींव कुछ महीनों पहले ही सोशल मीडिया पर पड़ी थी। यह आंदोलन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके फ्रांस्वा बायरो की बजट नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ था।

नेपाल हिंसा में सेना ने मोर्चा संभाला, अंतरिम सरकार की चर्चा तेज

भारत की हालात पर नजर, कई राज्यों के लोग नेपाल में फसे

नेपाल की जेलों से अब तक 13,500 से ज्यादा कैदी भागे

एजेंसी

काठमांडू, नेपाल में GenZ प्रदर्शन ने देश की सरकार को गिरा दिया है। युवाओं के प्रदर्शन की आग बुधवार को अपेक्षाकृत शांत दिखी, लेकिन सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सेना स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति पूर्वक अपने घरों में रहने की अपील कर रही है। नेपाल सेना ने बुधवार को देशव्यापी प्रतिबंधात्मक आदेश और कर्फ्यू लागू किया। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद करना पड़ा, जिससे सैकड़ों विदेशी यात्री फस गए. हालांकि शाम छह बजे से उड़ानें फिर शुरू कर दी गई

अब देश में अंतरिम सरकार की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच नेपाल की पहली महिला पूर्व चीफजस्टिस सुशीला कार्की का नाम सामने आया था हालांकि बाद में खबरें आई कि अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। आपको बता दें कि सुशीला कार्की को महाभियोग लाकर चीफ जस्टिस पद से हटाया - सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल काफी छोटा रहा। कार्की 11 जुलाई 2016 से 06 जून 2017 तक नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की चीफजस्टिस रहीं। सुशीला कार्की को उनके पक्षपातपूर्ण फैसले देने के आरोप में चीफ जस्टिस पद से हटा दिया गया था। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।

बीएचयू की छात्रा रहीं सुशीला कार्की का परिचय

काशी हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र की परास्नातक और नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सुशीला कार्की ने श्रीमती सुशीला कार्की जन्म 7 जून 1952, विराटनगर, नेपाल में हुआ है। उन्होंने वर्ष 1975 में बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की थी। वहीं उनकी नियुक्ति की जानकारी होने के बाद परिसर में उनकी चर्चा भी खूब होती रही। उनके बतौर नेपाली प्रधान मंत्री के तौर पर नियुक्ति किए जाने संबंधी जानकारी के बाद परिसर में खूब गहमागहमी शुरू हो गई।

नेपाल में सुप्रीम कोर्ट में 60,000 फाइलें जलीं, हथियार लूटे

काठमाण्डू, काठमांडू में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) यानी सिंह दरबार पिछले कई घंटे से जल रहा है। यहां की आग बुझाने की अग्निशमन विभाग की कोशिशें नाकाम दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई विभाग आग में जलने से 60,000 फाइलें जलकर राख हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक, राणा काल में निर्मित दरबार अभी जल रहा है। दरबार के पश्चिमी हिस्से में आग की लपटे उठ रही हैं। हालांकि, मंत्रालयों की आग बुझ गई है। यहां 40 से अधिक दमकल गाड़ियां लगी हैं, लेकिन 3,500 लीटर क्षमता वाली एक गाड़ी का पानी 10 मिनट में खत्म हो रहा है, लेकिन आग नहीं बुझ रही। जेन-जेड प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार दोपहर 3 बजे दरबार को जलाया था। दरबार परिसर में खड़ी सभी गाड़ियां जल चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की आग बुधवार सुबह तक नहीं बुझी है।

भारतीय छात्रों को कनाडा से झटका 2025 में 80प्रतिशत वीज़ा आवेदन खारिज

नई दिल्ली/टोरंटो एजेंसी

अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा प्रवासी छात्रों और एच-1बी वीजा धारकों पर सख्ती के बाद अब कनाडा ने भी भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा प्रक्रिया कड़ी कर दी है। कनाडा की इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा के अनुसार, 2025 में 80 प्रतिशत भारतीय छात्र वीज़ा आवेदनों को खारिज कर दिया गया है, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक है। कनाडा सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में केवल 1.88 लाख भारतीय छात्रों को ही एडमिशन मिला, जबकि यह संख्या दो साल पहले लगभग दोगुनी थी। इस गिरावट का असर वहां के कॉलेजों में नामांकन पर भी पड़ा है।

कनाडा में वीज़ा अस्वीकृति दर बढ़ने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख कारण आवासीय सुविधा की भारी कमी, बुनियादी ढांचे पर बढ़ता दबाव स्थानीय राजनीति का असर, नए और सख्त वीज़ा नियम हैं। अब वीज़ा आवेदन करने वाले छात्रों को कम से कम 20,000 कनाडाई डॉलर की वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही विस्तृत अध्ययन योजना और भाषा परीक्षा के प्रमाणपत्र भी आवश्यक होंगे। इस बदलाव के चलते भारतीय छात्रों का रुझान अब कनाडा और अमेरिका से हटकर अन्य विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। खासतौर पर जर्मनी एक नया प्रमुख शैक्षणिक गंतव्य बनकर उभरा है। एडटेक कंपनी अपग्रेड की ट्रांसनेशनल एजुकेशन (TNE) रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार जर्मनी को 31 प्रतिशत छात्रों ने अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि 2022 में यह आंकड़ा केवल 13.2 प्रतिशत था।

CMYK CMYK

जीएसटी सुधार से आमजनता, व्यापारी व किसानों को मिलेगा सीधा लाभ - भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

आमजन का जीवन होगा खुशहाल, व्यापार उद्योग को मिलेगी नई गति - भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह

जगदलपुर, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव ने कहा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार करके रेट को कम करके भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। श्री देव ने कहा कि यह बदलाव आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक बढ़त होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण सिंह देव आज मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्र वार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले तक भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे। इसके अलावा राज्य सरकारें भी मनमाने ढंग से कभी भी कोई भी कर आरोपित कर देती थी। पिछले वर्ष 12 लाख सालाना की आय पर टैक्स नहीं लागू करने का निर्णय लेने के बाद अब जीएसटी में चार स्लैब के बदले दो ही स्लैब रखने, सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य करने और अनेक उत्पादों में कर 10 प्रतिशत तक कम कर देने से अब वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था अब जनता के लिए रामराज्य लाने वाला साबित होगा। श्री देव ने कहा कि नए सुधार से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की अनेक वस्तुएँ, ट्रैक्टर व उसके कलपुर्जे व अन्य कृषि उपकरण तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, शैक्षणिक वस्तुओं के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल उत्पादों को किफायती बनाया गया है। जीएसटी करदाता 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ हो गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो केवल चार वर्षों में दोगुना हो गया है। इसका लाभ वस्त्र उद्योग को, विशेष रूप से निर्यात के लिए, होगा। हस्तशिल्प की कम दरें कारीगरों की आजीविका को समर्थन देंगी, विरासत को संरक्षित करेंगी और ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। ऑटोमोटिव में स्पष्ट वर्गीकरण से विवाद कम होंगे तथा विनिर्माण और निर्यात में वृद्धि को समर्थन मिलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि यह सुधार किसानों के जीवन में भी आर्थिकी को मजबूती प्रदान करेगा और यह किसान के लिए कम लागत के साथ सक्षम कृषि में सहायक होगी। इसके अलावा अपवाद के रूप में जहां स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर 40 प्रतिशत कर आरोपित किया गया है, वहीं बीड़ी को 18 प्रतिशत के स्लैब में ही रखा गया है। इससे भविष्य में तेंदू पत्ता संग्राहकों को काफी लाभ होगा। जनजातीय क्षेत्र में तेंदू पत्ता जैसे लघु वन्य उत्पादों की मांग अधिक बढ़ेगी, इससे प्रदेश को भी काफी लाभ होगा। श्री देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक सुधार और शानदार प्रबंधन के लिए केवल प्रोत्साहन राशि के मद में 6200 करोड़ रुपए मिले हैं। छत्तीसगढ़ की आबादी देश की जनसंख्या का दो

अज्ञात वाहनों से कुचल कर पांच गौवंशों की दर्दनाक मौत

0 कलेक्टर के निर्देश के बाद भी गौवंश की सुरक्षा पर किसी का नहीं है ध्यान

जगदलपुर, रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर अज्ञात वाहन ने तीन गौवंशों कोकुचल डाला। इसी हाईवे पर ही और दो गौवंश की मौत हुई है। एक रात में पांच गौवंश की मौत की घटना दिल दहलाने वाली है।

इंद्रावती पुल के आगे ट्रैक्टर शो रूम के सामने तीनों गौवंशों को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला। तीनों मवेशियों की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसी मार्ग पर आसना में कल रात दो गौवंशों को अज्ञात वाहन ने कुचल कर मार डाला था।एक ही रात में पांच गौवंशों की दर्दनाक मृत्यु हो गई और जिम्मेदार मौन हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरेआम रौंदी जा रही है गौमाता। इस घटना से व्यथित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दोनों घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और वाहन चालकों को नसीहत दी है कि वे गौवंश को सुरक्षित बचाते हुए वाहन चलाएं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में सड़कों पर बैठे मवेशियों की सुरक्षा के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए थे। इसके अलावा जगदलपुर के महापौर संजय पाण्डेय ने भी बेसहारा घूमने वाले और सड़कों पर बैठे रहने व विचरण करने वाले मवेशियों की सुरक्षा के लिए कांजी हाउस को दुरुस्त करवाया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी बेसहारा गौवंशों को गौशालाओं में सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं।

किरायेदार छात्र के घर में चोरी मामले में नाबालिक बाल संप्रेषण गृह भेजा गया

पुलिस ने नाबालिक अपचारी बालक को लिया हिरासत में, भेजा बाल संप्रेषण गृह

नाबालिक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध थाना कुनकुरी में बी एन एस की धारा 331(3),305(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध

जशपुर । नाम आरोपीः-17 वर्षीय विधि से संघर्षरत बालक। पुलिस ने नाबालिक बालक के कब्जे से चोरी की कपड़े, आधार कार्ड व 300रु को भी किया जप्त जशपुर, 09 सितंबर (आरएनएस)। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.09.2025 को प्रांजल ठाकुर उम्र 21 वर्ष, निवासी ब्रह्म रोड अंबिकापुर, वर्तमान निवास डुगडुगीया कुनकुरी , में किराए के मकान में रहकर बीएससी, हार्टिकल्चर की पढ़ाई करता है, के द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि वह घटना दिनांक 07.09.25 को प्रातः 04.00 बजे, प्रतिदिन की भांति मॉर्निंग वॉक/दौड़ने , अपने किराए के घर को ताला बंद कर , पंडरी पानी, पहाड़ मुड़ा रोड में निकाला था, जो कि दौड़कर वापस आने पर देखा कि उसके किराए के मकान का ताला टूटा हुआ था व व कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था, साथ ही कमरे के अंदर उसके बैग से शर्ट, पैंट, तथा पैंट में रखा पर्स, जिसमे की प्रार्थी का एक हजार रु व आधार कार्ड था, उसे भी किसी के द्वारा चुरा लिया गया था। रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में चोर के विरुद्ध बी एन एस की धारा 331(3),305(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा उक्त कृत्य को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पता साजी हेतु, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था, साथ ही चोरी के कपड़े के संबंध में भी मुखबिरों को अवगत कराया गया था, और पुलिस लगातार संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबीर से पता चला कि डुगडुगिया निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिक बालक, पुलिस द्वारा बताए अनुसार चोरी के कपड़े, जैसा शर्ट पहनकर घूम रहा है, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल संदिग्ध नाबालिक को हिरासत में लिया गया। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी नाबालिक बालक के द्वारा अपना कृत्य स्वीकार करते हुए बताया गया कि उक्त घटना दिनांक को सुबह जब वह टहल रहा था, तो देखा कि एक किराए के घर से एक व्यक्ति, अपने घर को ताला बंद कर, दौड़ने के लिए निकल रहा था>

बालोद में एनएचएम संविदा कर्मचारियों का जल सत्याग्रह, नियमितीकरण की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी

बालोद । छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (ह्॥रू) के संविदा कर्मचारी अपनी नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ह्॥रू कर्मचारी संघ के बैनर तले ये आंदोलन अब 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है। मंगलवार को कर्मचारियों ने अपने विरोध को एक नया रूप देते हुए जल सत्याग्रह का सहारा लिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारी रैली की शक्ल में तांदुला डेम पहुंचे और वहां तांदूला नदी के पानी में बैठकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अपने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। जल देवता से यह कामना की गई कि शासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे और जल्द ही समाधान निकाले। कर्मचारियों का कहना है कि वे अब सरकार के केवल आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे। यदि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। इसी क्रम में खैरागढ़ जिले के ह्॥रू कर्मचारियों ने भी समर्थन में मोर्चा संभालते हुए अम्बेडकर चौक से रैली निकाली और दाऊ चौरा स्थित मुसका नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया। कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और स्पष्ट कहा कि जब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

बस्तर में सतत विकास लक्ष्य के डैशबोर्ड में डेटा एंट्री पर कार्यशाला

जगदलपुर । प्रदेश सरकार के सतत विकास लक्ष्यों और छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग स्तरीय एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से नव विकसित सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड में डेटा प्रविष्टि के संबंध में आयोजित किया गया है।कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह ने बताया कि यह कार्यशाला शुक्रवार 12 सितम्बर को सुबह 10 बजे से कुम्हरावंड स्थित शहीद गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संभागीय स्तर पर सभी जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों तथा विभिन्न विभागीय अधिकारियों को सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड पर डेटा एंट्री का प्रशिक्षण देना है। यह डैशबोर्ड राज्य की विकास योजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होगा।

शासकीय पॉलीटेक्निक बीजापुर में रजत जयंती वर्ष 2025-26 के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन

बीजापुर, 09 सितंबर (आरएनएस)। जिले के एकमात्र इंजीनियरिंग संस्थान शासकीय पॉलीटेक्निक बीजापुर में रजत जयंती वर्ष 2025-26 के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया।कार्यक्रम की शुरुआत नवप्रवेशित विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों एवं रूपरेखा से अवगत कराते हुए सखी वन सेंटर की कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों को लैंगिक उत्पीड़न, महिला अधिकार एवं जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। छात्र-छात्राओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु मनोरंजक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुर्सी दौड़, नींबू-चम्मच दौड़ तथा मेहंदी सजाओ प्रतियोगिता शामिल थीं। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।

इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम के तहत वृक्षारोपण किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

यह आयोजन संस्था के प्राचार्य श्री सी.के. राहंगडाले के मार्गदर्शन में एवं कार्यक्रम प्रभारी व्याख्याता श्री संदीप कुमार सोनी के संचालन में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

समय-सीमा बैठक : विकास कार्यों और योजनाओं पर कलेक्टर ने दिए निर्देश

रजत महोत्सव पोर्टल पर प्रविष्टि अपलोड करने विभागों को निर्देश

धमतरी। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में आज समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि रजत महोत्सव पोर्टल पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों, 25 वर्षों की उपलब्धियों और जनसहभागिता से जुड़ी प्रविष्टियाँ अपलोड की जाएं।

अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं को जागरूक करने पर जोर

कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि आगामी जनवरी माह में धमतरी जिले में भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। यह कई वर्षों बाद जिले में होने जा रही है। उन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालयों में पात्र युवाओं को पंजीयन हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए।

पंचायतों की आय वृद्धि और सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने पर बल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रोमा श्रीवास्तव को पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए कर वसूली करने तथा बड़े ग्राम पंचायतों के चौक-चौराहों पर विशेष सफाई व्यवस्था करने कहा।शिक्षा विभाग को पुस्तक वितरण और तिमाही परीक्षा की तैयारी के निर्देश

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यार्थियों को समय पर पुस्तक वितरण और आगामी माह के प्रथम सप्ताह से तिमाही परीक्षा शुरू कराने कहा।वन विभागीय प्रकरणों के त्वरित निराकरण की अपीलवनमंडलाधिकारी श्री जाधव श्रीकृष्ण ने कहा कि विभागीय अधिकारी यदि समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करेंगे तो जिला स्तर से संबंधित कार्यों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा।जनगणना 2027 पूर्णतः डिजिटल होगी बैठक में बताया गया कि वर्ष 2027 में भारत की जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का होगा जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना का होगा। एसडीएम, तहसीलदार और सीएमओ नगरपालिका को समय पर जानकारी देने के निर्देश दिए गए।

नुक्कड़ नाटक और लोक संस्कृति के माध्यम से जनजागरूकता अभियान

ग्रामीणों तक पहुँचेगी साक्षरता और शासकीय योजनाओं की जानकारी

सुकमा । कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कला जत्था प्रशिक्षण का आयोजन आदिवासी भवन, सुकमा में दिनांक 01 से 05 सितम्बर तक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, स्वास्थ्य, विभागीय योजनाओं तथा नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाना है। प्रशिक्षण का नेतृत्व अनुभवी प्रशिक्षक श्री हीरा मानिकपुरी (नेशनल स्कूल ड्रामा) ने किया, जबकि लीड अर्कजा कुठियाला पीपीआईए फेलो द्वारा दिया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, नृत्य और मातृभाषा में संवाद जैसे प्रभावशाली सांस्कृतिक माध्यमों का प्रशिक्षण दिया गया ताकि आम नागरिकों तक सरल भाषा और स्थानीय परंपराओं के साथ सरकारी योजनाओं का संदेश पहुँच सके। प्रशिक्षण के पश्चात प्रतिभागियों को हाट-बाजार, गाँवों और जनसमूहों में जाकर जागरूकता अभियान चलाने निर्देशित किया गया। इस पहल से न केवल योजनाओं की जानकारी व्यापक स्तर पर फैलेगी, बल्कि ग्रामीण समुदाय में आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य संरक्षण और नशा मुक्ति की दिशा में सकारात्मक बदलाव आएगा। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जनजागरूकता अभियान प्रभावी होता है। जिला प्रशासन की यह पहल ग्रामीणों को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुन्द ठाकुर ने प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आपकी सहभागिता से विकास योजनाएँ सीधे लोगों तक पहुँचेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी.आर. मंडावी, जिला परियोजना अधिकारी श्री उमाशंकर तिवारी, नोडल अधिकारी अगस्टिन कुमार राम, गजेन्द्र कुमार देशमुख तथा रविन्द्र कुमार नायक का विशेष सहयोग रहा।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे पहुँचे ऑयल पाम के खेत, किसानों को दी स्थायी आमदनी की राह

जांजगीर-चांपा । जिले के बम्हनीडीह विकासखंड के ग्राम सोंठी में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने रविवार को ऑयल पाम की खेती का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर खेती के लाभ बताए और कहा कि ऑयल पाम फसल किसानों के लिए दीर्घकालिक आय का मजबूत साधन बन सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर पौधरोपण, सिंचाई, तकनीकी मार्गदर्शन और सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। साथ ही शुरुआती वर्षों में किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए अंतरवर्ती फसलों की खेती पर भी सहायता दी जा रही है। जांजगीर। कलेक्टर ने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा कि जिले में ऑयल पाम की खेती को विशेष अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा

किसान इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने उद्यानिकी और कृषि विभाग को निर्देश दिए कि स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के दौरान उप संचालक कृषि ललित मोहन भगत, सहायक संचालक उद्यानिकी श्रीमती रंजना मखीजा, कृषक पुरुषोत्तम शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी खेमा दस महंत, चूड़ामणि राठौड़, धर्मपाल राठौड़, कृषि विभाग के अधिकारी, स्थानीय किसान और महिला समूह की सदस्य मौजूद रहे। सहायक संचालक उद्यानिकी ने बताया कि जिले में ऑयल पाम खेती का 500 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 29 हजार रुपये मूल्य के 143 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पौधरोपण, फेंसिंग, सिंचाई और अंतरवर्ती फसलों की लागत करीब चार लाख रुपये आती है। इस पर केंद्र सरकार द्वारा 1.30 लाख रुपये और राज्य शासन द्वारा 1.29 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही अंतरवर्ती फसल, बोरवेल, पंप सेट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर भी अनुदान का प्रावधान है।

ऑयल पाम की फसल तीसरे साल से उत्पादन देना शुरू करती है और लगभग 25 से 30 साल तक लगातार उपज देती है। एक हेक्टेयर से हर साल करीब 20 टन उपज प्राप्त होती है जिससे किसान को ढाई से तीन लाख रुपये तक की सालाना आय संभव है।

सेंट्रल एवेन्यू रोड पर हेलमेट अनिवार्य, यातायात पुलिस की विशेष कार्यवाही आरंभ

भिलाई। भिलाई की सेंट्रल एवेन्यू रोड (मुर्गा चौक से सेक्टर 9 चौक तक) पर यात्रा के दौरान हेलमेट पहनना सभी दोपहिया वाहन चालकों एवं सवारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। यह सम्पूर्ण मार्ग ग्रे स्पॉट क्षेत्र में चिन्हित है, जहाँ लगातार सड़क दुर्घटनाएँ, रैश ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण, प्रेशर हॉर्न का दुरुपयोग एवं तीन सवारी के गंभीर मामले सामने आ रहे थे। इसके साथ ही जिले भर में कलेक्टर दुर्ग के आदेशानुसार नो हेलमेट ङ्क नो पेट्रोल नीति लागू की गई है, जिससे हेलमेट उपयोगिता को बढ़ावा मिले एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। इस क्षेत्र में वाहनों की संख्या प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना और अधिक बढ़ गई है। स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया है, तथा रेल चौक सेक्टर-6, मुरगा चौक सेक्टर-1, डीपीएस चौक एवं सेक्टर-8 चौक पर विशेष हेलमेट चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया है।

अभियान के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों पर सख्त कार्यवाही करते हुए चालानी कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान सतत् रूप से जारी रहेगा तथा आगामी दिनों में इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर लाईवलीहुड कॉलेज में आयोजित हुआ सेमीनार

धमतरी। छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर 8 सितम्बर को लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में उद्यमिता विकास, डिजीटल एवं वित्तीय साक्षरता विषय पर सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में लाईवलीहुड कॉलेज के विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सौ से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सहायक परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हुए वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग लेनदेन, डिजीटल एवं साईबर ठगी से बचाव, उद्यमिता विकास तथा स्टार्टअप जैसे विषयों पर उपयोगी जानकारी दी। प्रशिक्षणार्थियों ने विशेषज्ञों से प्रश्न पूछकर अपने संदेहों का समाधान किया तथा सेमीनार को अपने भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री प्रशांत चन्द्राकर, भारतीय स्टेट बैंक धमतरी शाखा प्रबंधक श्रीमती एकता मरकाम, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट काउंसलर, लीड बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा धमतरी के अधिकारी उपस्थित थे। सेमीनार का सफल संचालन किया गया तथा सहायक परियोजना अधिकारी, लाईवलीहुड कॉलेज श्री संदीप कुमार गोन्नाडे ने आभार व्यक्त किया।

मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गएः-

1) मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

2) मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

नीति की अवधि - नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।

उद्योगों को मिलने वाले लाभ - सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।

इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है।

3) मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सुश्री रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।

प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां के तहत शासकीय कर्मचारियों ने अपने जन्मदिन पर बच्चों के संग साझा की खुशियां

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित अभिनव पहल प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां के तहत रायपुर जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी अब अपने जन्मदिवस को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए नन्हें बच्चों संग खुशियां बांट रहे हैं। इसी कड़ी में लेक्चरर श्री भीखम राम साहू तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुपरवाइजर श्री उभय राम साहू ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आंगनबाड़ी तथा स्कूली बच्चों के साथ विशेष समय बिताया। दोनों अधिकारियों ने बच्चों के साथ केक काटा तथा उन्हें फल, मिठाई, पौष्टिक आहार वितरित की। इस पहल के तहत कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह द्वारा जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एसएमएस और ई-कार्ड के माध्यम से शुभकामनाएं भेजी जाती हैं और उन्हें पास के आंगनबाड़ी या विद्यालय में बच्चों संग जन्मदिन मनाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

अपने अनुभव साझा करते हुए दोनों कर्मचारियों ने कहा, बच्चों के साथ जन्मदिन मनाना हमारे लिए अत्यंत सुखद अनुभव रहा। समाज से जुड़कर अपनी खुशियां बांटना एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट फिर हैक : पाकिस्तानी हैकर्स ने मचाई सनसनी,

दुर्ग। दुर्ग जिले के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट फिर से हैक होने की खबर सामने आई है। इस बार इस घटना को पाकिस्तानी हैकर्स ने अंजाम दिया है। यह एक महीने के अंदर तीसरी बार है जब विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक हुई है। सोमवार को जब छात्र वेबसाइट खोल रहे थे, तो उन्हें वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर दिखे।

हैकिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हैकर्स ने ली है और उन्होंने वेबसाइट पर भारत का मजाक उड़ाने वाले पोस्ट भी डालें। इस घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन और वेबसाइट की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली निजी कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, छात्र लगातार हो रही इस हैकिंग पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रबंधन से जवाब मांग रहे हैं। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला विश्वविद्यालय की सुरक्षा में बड़ी चूक को दर्शाता है।

द्वितीया श्राद्ध पर परिजनों ने पितरों का किया तर्पण :रायपुर । आज द्वितीय श्राद्ध के अवसर पर परिजनों ने नदी घाट पर पहुंचकर पानी में विधि अनुसार अपने परिवार के पुरखों को सादर नमन करते हुए तर्पण किया। द्वितीया श्राद्ध के अवसर पर राजधानी सहित प्रदेश भर में वंशजों द्वारा अपने पूर्वजों को जल तर्पण के साथ ही अक्षय सुखों की प्राप्ति के लिए हाथ जोड़कर निवेदन किया गया। जिन पूर्वजों की द्वितीया तिथि पर मृत्यु हुई थी। उनका पूजन पाठ कर विधि अनुसार कुत्ता गाय एवं कौआ का हिस्सा उन्हें खिलाकर परिजनों को भोजन कराया गया।

स्वर्गीय विनय शर्मा स्मृति फोटो ग्राफी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण आज

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा स्व. विनय शर्मा स्मृति फोटोग्राफी प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी के समापन अवसर पर आज शाम छह बजे रायपुर प्रेस क्लब मोतीबाग में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। उक्त समारोह के मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अध्यक्षता पुरंदर मिश्रा विधायक रायपुर उत्तर विधानसभा एवं विशिष्ट अतिथि संपादक छत्तीसगढ़ वाच रामावतार तिवारी होंगे।

एनएचएम कर्मियों का दस सूत्रीय मांगों को लेकर धरना जारी, पांच मांगे पूर्ण होने का शासन का दावा भ्रामक

मांगे पूर्ण नहीं होने पर जिला मुख्यालयों में कर्मी करेंगे जल सत्याग्रह

रायपुर। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16 हजार कर्मी नियमितिकरण संविलियन सहित दस सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 18 जुलाई से तूता धरनास्थल नया रायपुर में धरना दे रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश के प्रांताध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं प्रदेश सरकार द्वारा जान बुझकर दस सूत्रीय मांगों को उपेक्षित किया जा रहा है। हाल ही में शासन द्वारा यह दावा किया गया कि कर्मियों की पांच मांगे पूर्ण कर दी गई है। जबकि वस्तुस्थिति ये है कि एक भी मांग शासन द्वारा पूरी नहीं की गई है। शासन की हठधर्मिता के चलते जहां प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। 16 हजार कर्मियों की एक साथ धरना दिये जाने के फल्स्वरूप शहरों में भी जिला मुख्यालयों में स्थित जिला चिकित्सालयों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मरीज रोज इलाज के लिए केंद्रों में आकर भटक रहे हैं। डॉ. मिरी ने चर्चा के दौरान बताया कि दस सूत्रीय मांगों के तहत संविलियन जॉब सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ केडर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, कार्यमूल्यांकन पद्धति में सुधार, लंबे समय से लंबित 27 प्रतिशत वेतनवृद्धि नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण अनुकंपा नियुक्ति मेडिकल या अन्य अवकाश की सुविधा स्थानांतरण नीति अचानक दुर्घटनाग्रस्त अथवा बीमारी से ग्रस्त होने पर दस लाख रुपये की बीमा योजना लागू करने की मांग की है। जिनमें से शासन द्वारा 27 प्रतिशत वेतनवृद्धि की घोषणा 19 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के लगभग 37हजार कर्मियों के लिए की गई थी जिनमें 16 हजार एनएचएम कर्मी भी शामिल थे। वह वृद्धि भी आज तक प्राप्त नहीं हुई है। डॉ. अमित ने बताया कि उक्त मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो जिला मुख्यालयों में प्रदेश के 16 हजार एनएचएम कर्मी जल सत्याग्रह करेंगे।

नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की मुख्यमंत्री ने

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान तथा विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार यूनिफाइड कमांड के प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ने हाल ही में नक्सलियों के सफाया की चर्चा करते हुए कहा कि हमें यह अभियान और तेज करना है। ज्ञात रहे छत्तीसगढ़ शासन के पुलिस बल एवं केन्द्रीय पुलिस बल सहित अन्य बलों में दंतेवाड़ा, बीजापुर में अनेक दुर्गमस्थलों में नक्सली कैम्प का सफाया किया है तथा कई शीर्ष नेताओं ने आत्मसमर्पण किया है। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित झांकियों ने लोगों का मन मोहा

रायपुर। राजधानी में बीती रात श्रद्धा और शॉर्य का संगम देखा गया। रात में पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां निकली। जिसे देखने के लिए जनसैलाब टुट पड़ा। डीजे के साथ लोग थिरकते हुए मालवीय रोड से सदरबाजार होकर निकले।

राजधानी में राजनांदगांव तथा अन्य स्थानों से झांकियां दोपहर से आना शुरू हुई थी। शारदा चौक पहुंचने पर उन्हें टोकन दिया गया। उसके बाद झांकियां एक-एक करके निकलने लगीं। आकर्षक बैंड बाजे और डीजे के धूनों के साथ भक्त नाचते कुदते हुए निकले। पुलिस की व्यापक व्यवस्था होने के बावजूद भी जमकर चाकू बाजी हुई। गोलबाजार थाने में आज सुबह रिपोर्ट करने

वालों का तांता लगा रहा। झांकियों में भगवान नरसिंह अवतार, शिव पूजन तथा मुसक की सवारी आकर्षण का केन्द्र बनी रही। राजधानी शहर रायपुर में श्रीगणेश मूर्ति विसर्जन चल झांकी का रायपुर नगर पालिक निगम के मंच पर विसर्जन रूट में नगर निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल, राज्य लौह शिल्पकार विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, नगर निगम संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, एमआईसी सदस्य महेन्द्र खोडियार, अवतार भारती बागल, भोलाराम साहू, नंदकिशोर साहू, दीपक जायसवाल, श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, श्रीमती सुमन अशोक पाण्डेय, जोन 5 अध्यक्ष श्री अंबर अग्रवाल, पार्षद श्री कृष्णा सोनकर, श्री आनंद अग्रवाल, अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय, उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा, जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव सहित निगम जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने आमजनों सहित पुष्पवर्षा कर आत्मीय स्वागत किया.महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित रायपुर नगर निगम के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने प्रथम पूज्य देव भगवान श्रीगणेश के दिव्य श्रीचरणों में राजधानी रायपुर शहर रायपुर को स्वच्छ, हरित, विकसित स्मार्ट सिटी बनाने कार्य करने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्रदान करने और सभी नगरवासियों के जीवन में शुभत्व सहित सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शान्ति प्रदान करने हेतु विनम्र प्रार्थना की।

कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई पर पायलट ने कहा-एकजुट होकर लड़ेंगे 2028 का चुनाव, व्यक्ति विशेष का नहीं है मामला

डबल इंजन की सरकार केवल धुआं फेक रही, जनता का काम नहीं कर रही

रायपुर । कांग्रेस में चुनाव नेतृत्व को लेकर चल रही लड़ाई पर छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, 2028 का चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। सभी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। भापजा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार केवल धुआं फेक रही है। जनता के परेशानियों का काम नहीं कर रही है।

बिलासपुर में आज होने वाले 'वोट चोरी' को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में कहा, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने तमाम तथ्य रखे हैं। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट नहीं देने का कानून बदल दिया। यह तमाम चीजे दर्शाती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसको लेकर आगे भी खुलासा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताएंगे कि कैसे वोट चोरी हो रही है, इसके बाद

कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी।

राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश : वहीं यूनिफाइड कमांड की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इसमें बीजेपी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती है। इस मामले में ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाता है, पर काम कैसे हो रहा है। इस बात की पारदर्शिता रहनी चाहिए।

धनखड़ के इस्तीफे की पोल कभी न कभी खुलेगी : उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वहीं सचिन पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि देश की जनता जान नहीं पाई है कि पूर्व उपराष्ट्रपति अभी कहां हैं। अचानक उन्होंने क्यों पद त्याग दिया? धनखड़ साहब बहुत दबंग व्यक्ति हैं। लंबे समय से हम उन्हें जानते हैं। क्या कारण है कि अचानक वह चुप हो गए? सच्चाई क्या है पद खाली क्यों किया गया? कभी ना कभी इसकी पोल जरूर खुलेगी, इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अच्छा समर्थन मिलेगा।

तेज रफ्तार टैंकर बना मौत का कारण

रायपुर, । दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। एक केमिकल से भरे टैंकर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जितेंद्र कुमार साहू के रूप में हुई है, जो गौतम नगर का निवासी था।

यह दर्दनाक हादसा देर रात करीब 3 बजे का है। बताया जा रहा है कि केमिकल से भरा टैंकर भिलाई के छावनी क्षेत्र से होते हुए शंकर नगर की ओर जा रहा था। उसी समय जितेंद्र कुमार अपने दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था। क्रांति चौक के पास बाइक अचानक स्किड हो गई, जिससे उसका दोस्त दूर जा गिरा, जबकि जितेंद्र सड़क पर गिर पड़ा। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहा टैंकर उसे रौंदता हुआ निकल गया, जिससे जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए टैंकर चालक को पकड़ लिया और इसकी सूचना डायल 112 को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर टैंकर को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना में जुटी है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

कर्मचारियों को मिल रहा डिजिटल दक्षता का प्रशिक्षण

रायपुर, । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप 'प्रोजेक्ट दक्ष' अब जिले के शासकीय कार्यों को नई पहचान और गति प्रदान कर रहा है। इस अभियान से अधिकारी-कर्मचारी डिजिटल सशक्तिकरण की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। आज कलेक्टोरेट स्थित बीपीओ मल्टीलेवल पार्किंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विभाग के शेष जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारियों शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कंप्यूटर और मोबाइल के मूल उपयोग, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ईमेल एवं अन्य आवश्यक ऑनलाइन टूल्स की जानकारी दी गई। प्रोजेक्ट दक्ष का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और प्रभावशीलता लाना है। इससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली और अधिक सरल, पारदर्शी एवं स्मार्ट बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

हमें भारतीय संविधान पर गर्व है

सीजेआई गवई का अवलोकन, मेहता का प्रतिबिंब और नेपाल के जनरल जेड-समर्थित सुशीला कार्की का उदय

न्यायिक आत्मनिरीक्षण के एक आकर्षक प्रदर्शन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ की आज की सुनवाई के दौरान, भारत के संवैधानिक ढांचे की ताकत और स्थिरता को रेखांकित करने के लिए भारत की सीमाओं के पार चल रहे नेपाल और बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल का आह्वान किया।

नेपाल में सीमा के पार, जनरल जेड प्रदर्शनकारी राजनीतिक मंच पर भड़क गए हैं, 8 सितंबर से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें संसद, राष्ट्रपति कार्यालय और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट सहित कई इमारतें आग की लपटों में घिर गई हैं, अब तक 30 से अधिक मौतें हुई हैं।

घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में, नेपाल के जेन जेड आंदोलन के 5,000 से अधिक सदस्यों ने वर्चुअल रूप से बैठक की और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना - परन्तु बाद में ऐसी खबर है कि संभवतः उन्हें स्वीकार नहीं है या सुशीला जी ने स्वयं ही इंकार कर दिया है। अर्थात अभी भी गतिरोध बना हुआ है।

भारत की केंद्रीय सरक़ार का प्रतिनिधित्व करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के अपने लोकतांत्रिक अतीत के साथ एक मार्मिक समानता खींची- विशेष रूप से, 1975 के आपातकाल। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने उस समय व्यापक सत्ता थोपी थी, लेकिन मतदाताओं ने ऐसा सबक सिखाया कि न केवल पार्टी हार गई, बल्कि वह सीट भी हार गईं। एक और सरकार आई, चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, ÷ प्रचंड बहुमत के साथ। इस पर मेहता ने कहा, 'हां, यह संविधान की शक्ति है। यह कोई राजनीतिक तर्क नहीं है। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में, नेपाल के Gen Z आंदोलन के 5,000 से अधिक सदस्यों ने वर्चुअल रूप से बैठक की और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना - नेपाल में उस पद को संभालने वाली पहली महिला।

सुशीला कार्की 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं। उनके कार्यकाल को हाई-प्रोफाइल फैसलों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए एक मौजूदा मंत्री की सजा और नागरिकता अधिकारों पर ऐतिहासिक निर्णय शामिल थे।

1975 में भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की।

न्याय और भ्रष्टाचार विरोधी के प्रति अपनी निडर प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 2017 में न्यायिक अतिरेक के आरोपों पर महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जो उनके साहसिक फैसलों का प्रतिबिंब है।

मुख्य न्यायाधीश गवई का नेपाल और बांग्लादेश का आह्वान संवैधानिक शासन की नाजुकता की एक ज्वलंत याद दिलाता है, जो भारत के सापेक्ष संस्थागत लचीलेपन के साथ जुड़ा हुआ है। इस बीच, नेपाल में जनरल जेड प्रदर्शनकारियों द्वारा सुशीला कार्की का समर्थन ईमानदारी में निहित निष्पक्ष नेतृत्व के लिए एक गहरी इच्छा का प्रतीक है - राजनीतिक निष्ठा में नहीं।

- प्रेमेन्द्र अग्रवाल।

सुशीला कार्की (मुख्य न्यायाधीश,नेपाल)

भारत के मुख्य न्यायाधीश

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन
PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp
Modimaya_ Vaidik_Netritva
Rashtriya Ekta
DLF-Vadra-Bhrasht Tantra
Silent Assassins Jan11,1966
Accursed & Jihadi Neighbour

सिंधु की पुकार : संप्रभुता की वापसी और गौरव की बहाली

अर्जुन राम मेघवाल

मानसून शब्द पूरे भारत में खुशी और गर्व का संचार करता है। यह नवाचार, नवीनीकरण और राष्ट्र के आर्थिक इंजन को तत्काल गति प्रदान करने का प्रतीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रचुर वर्षा के साथ मिलकर, इसकी नदियों को पुनर्जीवित करती है और देशभर में जल संसाधनों का विस्तार करती है। यह प्रगति के मौसम का प्रतीक है और स्वतंत्रता दिवस समारोहों के साथ मिला दिए जाने पर देशभक्ति की एक अनूठी भावना का संचार करता है। लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री के संबोधन ने एक बार फिर आकांक्षी नागरिकों के लिए एक ऐसा खाका पेश किया जो एक विकसित भारत के निर्माण के व्यापक लक्ष्य को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

संसद के इस विशेष मानसून सत्र की शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने इसे भारत का गौरवशाली सत्र बताया था। भारतीय सैनिकों का शौर्य, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारखानों पर निर्णायक प्रहार और सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का स्थगन–ये सब भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति के सबूत हैं और राष्ट्रीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। फिर भी, सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा के लिए सरकार के राजी होने के बावजूद, विपक्ष ने बाधा डालने का रास्ता चुना और व्यापक जनहित की कीमत पर विचार-विमर्श को राजनीतिक नौटंकी में सीमित कर दिया।

देश अरसे से स्वार्थ को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखने की कांग्रेस की पुरानी आदत का बोझ ढोता चला आ रहा है। विभाजन की दुखद विभीषिका से लेकर नेहरूवादी कूटनीति की महंगी पड़ने वाली विफलताओं तक, इतिहास गवाह है कि कैसे इन फैसलों ने भारत की मूल अवधारणा को ही कमजोर कर दिया। सिंधु जल संधि (1960) पर बारीकी से गौर करने पर, जनता और देश के विकास की कीमत पर तुष्टिकरण व अति-उदारता की एक ऐसी कहानी सामने आती है, जिसने राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं को निरंतर बाधित किया। यह घोर विडंबनापूर्ण है कि भारत के विकास से जुड़े हितों का त्याग एक ऐसे राजनीतिक आकलन से प्रेरित थे जिसने अपने नागरिकों के कल्याण से ऊपर पाकिस्तान के हितों को तरजीह दी।

मूल रूप से, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी), सिंधु नदी प्रणाली के जल का आवंटन पाकिस्तान के पक्ष में (80:20) करती है। सिंधु नदी प्रणाली का उद्गम मुख्य रूप से भारत में है। इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी में बहने वाली सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी महत्वपूर्ण नदियों पर नियंत्रण छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे वैसे व्यापक जल संसाधन छिन गए जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के विशाल शुष्क एवं सूखाग्रस्त इलाकों का कायाकल्प कर सकते थे। यदि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती, तो सुव्यवस्थित जल अवसंरचना इस इलाके के संपूर्ण विकास की तस्वीर को बेहतर बना सकती थी।

हालांकि, इस महत्वपूर्ण त्याग से व्यापक कूटनीतिक लाभ मिलने की उम्मीदें भ्रामक साबित हुईं। इस संधि के प्रक्रियात्मक संचालन ने चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन इसे दो महीने बाद, नवंबर में, संसद के समक्ष रखा गया और वह भी मात्र दो घंटे की औपचारिक चर्चा के लिए। जैसे ही इस संधि से जुड़े तथ्य सामने आए, इसके विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के बाद प्रमुख समाचार पत्रों में छपी प्रतिकूल टिप्पणियां सुर्खियों में छायी रहीं। इतने महत्वपूर्ण समझौते के प्रति संसदीय स्तर पर बरते गए इस जल्दबाजी भरे व्यवहार ने लोकतांत्रिक निगरानी, पारदर्शिता और तत्कालीन नेतृत्व की दुर्भावनापूर्ण मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

इस सीमित संसदीय पड़ताल के बावजूद, सिंधु जल संधि को भारतीय संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय एक युवा सांसद थे, ने चेताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नेहरू का यह तर्क बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण है कि पाकिस्तान की अनुचित मांगों के आगे झुकने से मित्रता और सद्भावना स्थापित होगी।

संसद में 30 नवंबर 1960 को हुई बहस से पता चलता है कि सभी दलों ने इस संधि की आलोचना की थी। अधिकांश सदस्यों ने सरकार की आलोचना की थी और उस पर पाकिस्तान के सामने झुकने तथा भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। राजस्थान से कांग्रेस सांसद श्री हरीश चंद्र माथुर, अशोक मेहता, ए.सी. गुहा, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद केटीके तंगमणि, सरदार इकबाल सिंह, बृजराज सिंह ने इस जल कूटनीति को लेकर स्पष्ट रूप से चिंताएं जाहिर की थी और इसके विफल होने से जुड़े नतीजों के बारे में अंदेशा जताया था। कुल मिलाकर, इस संधि को एकतरफा, न कि लेन-देन पर आधारित कहा जा सकता है।

इस संदर्भ में, यह विडंबना ही थी कि लोकसभा में अपने उत्तर के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने माननीय सांसदों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए और उन्हें कमतर भी आंका। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि संसदों द्वारा की गई आलोचना तथ्य और निहित विचारों से अनजान रहने पर आधारित है। उन्होंने (नेहरू) आगे कहा, मुझे इस बात का दुख है कि इतने महत्वपूर्ण मामले को... एक ऐसा मामला जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य से भी जुड़ा है... इतने हल्के में और इतनी लापरवाही एवं संकीर्ण सोच के साथ लिया जा रहा है।

इस संधि ने भारत के हितों को कुंद कर दिया और यह पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक उपलब्धि साबित हुआ। अयूब खान ने एक सार्वजनिक प्रसारण में स्वीकार किया था कि इस संधि की वैधता और गुण-दोष पाकिस्तान के विरुद्ध थे, लेकिन इस मामले में नेहरू की कूटनीतिक विफलता ने पाकिस्तान को बढ़त दिला दी। 4 सितंबर 1960 को रावलपिंडी में अपने प्रसारण में, अयूब खान ने कहा था, अब जो समाधान हमें मिला है, वह आदर्श नहीं है... लेकिन यह सबसे अच्छा समाधान है जो हमें इन परिस्थितियों में मिल सकता था, इनमें से कई बिंदु, चाहे उनके गुण-दोष और वैधता कुछ भी हों, हमारे खिलाफ हैं। ये खुलासे आज भी राष्ट्रीय हित को गौण रखने के पीछे के मकसद पर सवाल खड़े करते हैं।

जैसा कि निरंजन डी. गुलाटी ने अपनी किताब इंडस वाटर ट्रीटीः एन एक्सरसाइज इन इंटरनेशनल मीडिएशन में लिखा है, 28 फरवरी 1961 को खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने इस निराशा को स्वीकार करते हुए कहा थाः मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। इस संधि के बाद के घटनाक्रम में आया तीखा अंतर इस समझौते की असमानता को और भी गहराई से रेखांकित करता है। नेहरू की ढिलाई और राष्ट्रीय हित को दरकिनार करने की प्रवृत्ति समय के साथ भारी पड़ती गई। फरवरी 1962 में, 'वाशिंगटन पोस्ट' को दिए एक साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री नेहरू ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर को आगे की दिशा में एक बड़ा कदम और वास्तव में यह समझौता (कश्मीर के) क्षेत्रीय मुद्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण... बताया।

स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद, शांति और अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति की चाहत में कांग्रेस नेतृत्व ने भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा एवं समृद्धि के बजाय कूटनीतिक सुविधावाद को चुना। तुष्टिकरण की यह नीति कई मोर्चों पर राष्ट्रीय प्रगति के लिए हानिकारक साबित हुई। इस संधि से अपेक्षित मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक लाभ कभी भी साकार नहीं हुए। इसके उलट, यह युद्धों और निरंतर सीमा-पार तनावों के रूप में दुर्भाग्य लेकर आई। जल-बंटवारे की इस सख्त व्यवस्था ने सूखे से लड़ने, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करने और संवेदनशील इलाकों में कृषि को मजबूत करने हेतु अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की भारत की क्षमता को सीमित कर दिया। सत्ता-लोलुप शासकों ने आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की, जिससे भारत कमजोर हो गया। वास्तव में, यह संधि भारत के लिए जल कूटनीति की विफलता और पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक विजय थी।

अब, मोदी सरकार इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में एक और निर्णायक एवं साहसिक कदम उठा रही है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अंतिम रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना छोड़ नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट आह्वान राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी हैः आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते; पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते। यह कदम पिछली नीतियों से अलग हटकर एक साहसिक और ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह केवल एक कूटनीतिक पुनर्संतुलन भर नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों और किसानों के हितों एवं संबंधित हितधारकों की आजीविका के अवसरों की रक्षा करने के भारत के संप्रभु अधिकार का एक दृढ़ रणनीतिक दावा है - जो पाकिस्तान की ओर से आने वाले लगातार सीमा पार खतरों के सामने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को सर्वोपरि रखता है।

सिंधु जल संधि का स्थगन कूटनीति से कहीं आगे जाता है–यह विकासशील भारतञ्च2047 के लक्ष्य को साकार करने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। अपने जल संसाधनों पर नियंत्रण फिर से हासिल करके, भारत जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत कर सकता है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकता है–जोकि एक विकसित राष्ट्र बनने की कुंजी है। यह निर्णय पुराने समझौतों द्वारा थोपी गई सहमतियों का अंत करता है और जल संप्रभुता को प्रगति की बुनियाद के रूप में स्थापित करता है। यह एक ऐसा साहसिक कदम है, जो आत्मनिर्भरता, स्थिरता और समावेशी विकास के मिशन के साथ गहराई से जुड़ा है।

लेखक केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री, भारत सरकार हैं।

पांच वर्षों में कुछ नहीं बदला

शरुति व्यास

विडंबना है कि अफ़ग़ानिस्तान ने 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ उन मर्दों पर बरसीं जिन्होंने आधे देश को पिंजरे में कैद कर रखा है। तालिबान का शासन अब दूसरे दौर के पाँचवें साल में दाख़िल है। इन पांच वर्षों में कुछ बदला नहीं। वह दुनिया का इकलौता देश है जहाँ सत्ता पूरी तरह मर्दों के हाथ में है और औरतों को न केवल घरों में, पर्दे में जकड़ दिया है बल्कि उन्हें ग़ैर-ज़रूरी बना दिया है।

इक्कीसवीं सदी में भला कौन सोच सकता था कि पृथ्वी पर एक ऐसा राष्ट्र भी होगा जो आधी आबादी को बंद कर दे, औरतों को अदृश्य बना दे और उनकी अहमियत केवल बच्चों को जन्म देने में सीमित हो। यों दुनिया ने तालिबान को कूटनीतिक अछूत बना रखा है तब तक जब तक वे औरतों के प्रति अपना रवैया नहीं बदलें और अपने सर्व-मर्दाना पश्तून कैबिनेट को समावेशी नहीं बनाए। पर कोई फर्क नहीं पड़ा।। अफगान लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल के दरवाज़े बंद हैं। औरतें एनजीओ में काम नहीं कर सकतीं, पार्कों में नहीं जा सकतीं। स्वतंत्रता दिवस पर जिन छह जगहों पर फ़ूल बरसाए गए, उनमें से तीन पर औरतों की एंट्री मना थी।

काबुल में वह इस्लामी पुलिस सख़्ती से गश्त करती है जो नजर रखती है कि औरतें नक़ाब में हैं या नहीं? उनके साथ कोई पुरुष रिश्तेदार है या नहीं? शहर की कुछ बची हुई महिला एक्टिविस्टों में से एक ने साफ़ कहाः अफ़ग़ान औरतों की ज़िंदगी अब अनुमतियों की सीरिज में सिमट चुकी है। हर अनुमति मर्दों के हाथ में है। तालिबान को उनकी इसी हक़ीक़त के लिए सज़ा भी मिली है। वे प्रतिबंधित है, तिरस्कृत है और दुनिया में मान्यता से वंचित है।

बावजूद इसके दुनिया उनके साथ जीना सीख रही है। आक्रोश की जगह चुपचाप स्वीकार्यता ने ले ली है–मानो अफ़ग़ानिस्तान की तक़दीर अटल हो, और उसकी औरतें बलिदान योग्य। बड़े संकट और जगह हैं, ध्यान वहीं जा रहा है। नतीजा यह है कि वे ही देहाती मुल्ला जिन्हें कभी कलाश्निकोव लहराते जंगली कट्टरपंथी कहा गया, अब सिले-सिलाए पगड़ियों में चतुर कूटनीतिज्ञ बनकर लौटे हैं। उन्होंने दुनिया को अफ़ग़ानिस्तान बेचा है। उसके खनिज, उसके भूगोल, उसकी स्थिरता की संभावना के सौदे में आधी आबादी को ताले में रखे रखने का पक्का बंदोबस्त हो रहा है।

तालिबान को मान्यता मिलने लगी है। 15 अगस्त को पंखुड़ियों की बारिश से एक महीना पहले रूस पहला देश बना जिसने उसे आधिकारिक मान्यता दी। मास्को में इस्लामिक अमीरात ऑफ़ अफ़ग़ानिस्तान का झंडा फहराया गया। तालिबान ने 20 अगस्त को चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। 2024 में संयुक्त अरब अमीरात ने तालिबानी राजदूत स्वीकार किया, फिर जनवरी में चीन ने। अब कम से कम 15 देशों के राजदूत काबुल में हैं, अधिकतर क्षेत्रीय। कारोबार भी बढ़ रहा है–चीन, तुर्की और ईरान की कंपनियाँ सौदे कर रही हैं।

और फिर है प्रवासन संकट–जो अब सौदेबाज़ी का औज़ार है। समय के साथ हज़ारों अफ़ग़ान पड़ोसी और विकसित देशों में अवैध रूप से चले गए थे। 2023 में पाकिस्तान ने न केवल बिना पंजीकरण वाले अफ़ग़ानों को, बल्कि दस्तावेज़ रखने वालों को भी निकालना शुरू किया। अमेरिका ने हज़ारों अफ़ग़ानों से अस्थायी दर्जा छीन लिया। जर्मनी निर्वासन में तालिबानी राजनयिकों के साथ समन्वय कर रहा है। ताजिकिस्तान ने अफ़ग़ानों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। और एक राजनयिक के शब्दों मेंः तालिबान पश्चिम को शरणार्थी संकट का हल मुफ़्त में नहीं देगा।

भारत भी तालिबान के साथ सावधानी से चल रहा है–संवाद है,

अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की कुर्सी एक ही परिवार में क्यों

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी में इस समय पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) को लेकर काफी गंभीर मतभेद नजर आ रहे हैं। ऐसा इस लिये हैं क्योंकि पीडीए की बात करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश ने पार्टी के सभी प्रमुख पदों पर अपने परिवार के लोगों को बैठा रखा है। चुनाव के समय टिकट बांटते समय भी सपा आलाकमान सबसे पहले अपने और परिवार के बारे में ही सोचता है। यही वजह है मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहले मुलायम सिंह का कॉपीराइट हुआ करता था और उनके बाद उनके पुत्र अखिलेश यादव ने इन दोनों पदों को अपनी जागीर बना रखा है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी नेता के पद पर भी अखिलेश यादव काबिज हैं। मुलायम कुनबे के पांच सदस्य सांसद हैं। समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का पद एक ही परिवार तक सीमित रहता है। दो बार मुलायम सिंह और एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा कोई दूसरा सीएम नहीं बना। इससे आगे की बात की जाये तो मुख्यमंत्री होते हुए भी यह दोनों नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी विराजमान रहे। मुलायम कुनबे ने इन तीन पदों पर ना तो अपने से इतर कभी किसी पिछड़े समाज के नेता को आगे बढ़ाया ना ही दलित या फिर अल्पसख्यक नेता को इन पदों के लिये मौका मिला। ऐसे में अखिलेश का पीडीए छलावा ही नजर आता है। यही बात आज पार्टी से बाहर निकाली गई विधायक पूजा पाल कह रही हैं और इससे पहले भी कई नेता कह चुके हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पीडीए के अन्य नेता सीएम या पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि क्या समाजवादी एक परिवार तक सीमित होकर रह गई है। क्या पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव अन्य जातियों को धोखा दे रहे हैं?

गौरतलब हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनावों के बाद से पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को अपनी मुख्य रणनीति बनाया। अखिलेश ने इसे एक सामाजिक गठजोड़ के रूप में पेश किया, जहां पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देंगे। 2024 लोकसभा चुनावों में सपा की 37 सीटों की जीत को पीडीए की सफलता बताया गया। लेकिन पार्टी के भीतर उभरती कलह और कई नेताओं के बयान बताते हैं कि यह रणनीति महज एक चुनावी जुमला है, जिसके नाम पर अखिलेश अन्य बिरादरियों के नेताओं को धोखा दे रहे हैं। पीडीए में पी और डी को दरकिनार कर सिर्फ ए (अल्पसंख्यक, मुख्यतः मुस्लिम) पर फोकस करने के आरोप लग रहे हैं, जो पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के बयानों से पुष्ट होते हैं। यह स्टोरी इन आरोपों की पड़ताल करती है, जहां कलह की जड़ परिवारवाद, जातिवाद और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में छिपी है।

पार्टी के भीतर कलह की शुरुआत 2023-24 से ही दिखने लगी, जब पीडीए की घोषणा के बाद कई प्रमुख नेता से अलग हुए। सबसे बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जो पिछड़े वर्ग (कुर्मी) से आते हैं। मौर्य ने फरवरी 2024 में सपा छोड़कर अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई। उनके बयान में साफ कहा गया कि अखिलेश पीडीए के नाम पर पिछड़ों और दलितों को ठग रहे हैं। पार्टी में सिर्फ यादव और मुस्लिमों का बोलबाला है, अन्य जातियों को टिकट या पद नहीं मिलते। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा में परिवारवाद हावी है, जहां अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव और अन्य रिश्तेदारों को तरजीह दी जाती है,

जबकि के अन्य घटक सिर्फ वोट बैंक हैं। मौर्य के जाने के बाद सपा में हलचल मची, लेकिन अखिलेश ने इसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा करार दिया।

पिछड़े वर्ग से ही ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा पर हमला बोला। राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं, 2023 में सपा से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गये थे। अगस्त 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभर ने कहा, अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, लेकिन असल में उन्हें धोखा देते हैं।सपा नेता गायत्री प्रजापति, रामकांत यादव जेल में हैं, लेकिन अखिलेश सिर्फ एक जाति को बढ़ावा देते हैं। वे सभी जातियों से वोट लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हैं। राजभर ने पीडीए को फर्जी बताया और कहा कि अखिलेश ने कुम्हार समुदाय जैसे छोटे पिछड़ों को कभी महत्व नहीं दिया। राजभर के बयान से सपा में पिछड़ों की नाराजगी उजागर हुई, जो 2025 बाय-इलेक्शन में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है।

समाजवादी पार्टी में दलित बिरादरी भी असंतोष स्थिति में है। अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के आयोध्या से सांसद हैं, के करीबी मोईद खान पर 2024 में एक नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार का आरोप लगा। इस घटना ने पीडीए की साख पर सवाल उठाए। दलित नेता और पूर्व समाजवादी सदस्य रामजी लाल सुमन ने कहा कि अखिलेश ने 2012 में 2.5 लाख दलितों को डिमोट किया और 3 लाख बहुजन छात्रों की स्कॉलरशिप रोकी। सपा में दलितों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ नाम।सुमन ने राजपूत शासक राणा संगा को गद्दार कहने पर भी अखिलेश की आलोचना की, जो दलित-राजपूत गठजोड़ को तोड़ता है। हाल ही में विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाला गया। पाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश परिवारवाद चला रहे हैं, पीडीए सिर्फ दिखावा है। करहल में दलितों पर हमले और सीतापुर में दलित घरों को जलाने की घटनाएं समाजवादी पार्टी शासनकाल की याद दिलाती हैं, जहां दलित अपराध राष्ट्रीय औसत से 5 गुना ज्यादा थे।

अल्पसंख्यकों को छलने का आरोप सबसे गंभीर है। अखिलेश अपने परिवर के अलावा सिर्फ मुस्लिम नेताओं को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यह भी तुष्टिकरण का खेल है। मुलायम सिंह ने हर थाने में 3-4 मुस्लिम अधिकारी रखने का आदेश दिया, अखिलेश ने मुस्लिम लड़कियों को 20,000 रुपये की योजना चलाई। लेकिन संभल दंगों में सपा सांसद जिया उर रहमान पर आरोप लगा, फिर भी अखिलेश ने दंगाइयों के परिवारों को 5 लाख दिए, जबकि हिंदू पीड़ितों को कुछ नहीं। शैलेश यादव की हत्या पर चुप्पी साधी गई। सपा नेता जैसे जाहिद बैग, साजिद पाशा, मोईन खान पर अल्पसंख्यक समुदाय से ही बलात्कार के आरोप हैं, लेकिन पार्टी उन्हें बचाती है। अखिलेश मस्जिदों में मीटिंग करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, विकास नहीं। 2025 में स्कूल बंदी पर अखिलेश ने पीडीए शिक्षा पर हमला बताया, लेकिन उनके शासन में मुस्लिम क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार था।

अन्य बिरादरियों से भी नेता भागे। अपर्णा यादव (अखिलेश की भाभी) 2022 में बीजेपी में चली गई, आरोप लगाया कि सपा में महिलाओं और गैर-यादवों की कोई जगह नहीं। विरेंद्र बहादुर पाल पर बलात्कार का केस, रामेश्वर यादव पर जमीन हड़पने का आरोप ये सपा की छवि बिगाड़ते हैं। 2025 में ईडी रेड में सपा से जुड़े कारोबारी से 150 करोड़ मिले, जो उसका भ्रष्टाचार दर्शाता है। कुल मिलाकर, पीडीए अखिलेश के लिए चुनावी हथियार है, लेकिन पार्टी में कलह बढ़ रही है। नेता छोड़ रहे हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि अखिलेश यादव परिवार और मुस्लिम तुष्टिकरण में उलझे हैं, अन्य बिरादरियों को धोखा दे रहे हैं। अल्पसंख्यकों को भी सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है, बिना सच्चे विकास के। अगर यह जारी रहा, तो 2027 विधानसभा में सपा को बड़ा झटका लग सकता है। **यह निजी विचार है।**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सामाजिक, कल्याण और सुरक्षा क्षेत्रों में सुधार उपायों की पहचान के लिए परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया

पीआईबी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 9 सितंबर को सामाजिक, कल्याण और सुरक्षा क्षेत्रों में सुधार उपायों की पहचान पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक ने की। इस सत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सक्रिय भागीदारी की।

यह विचार-विमर्श, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सुधारों पर केंद्रित था जिनमें पोषण और ईसीसीई वितरण में सुधार, मिशन शक्ति - महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करना और मिशन वात्सल्य - बच्चों के समग्र विकास और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य रखे गए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों ने अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने तथा महिला एवं बाल-केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के लिए विधायी, नीति, प्रक्रियागत और संस्थागत सुधारों पर बहुमूल्य जानकारी साझा की। इस कार्यशाला के माध्यम से सहयोगात्मक सुधार उपायों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 'सबसे पहले महिला एवं बाल-बालिका' दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

लोक सभा अध्यक्ष बेंगलुरु में 11वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

लोकशक्ति

कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक के मुख्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँगे

पीआईबी

नई दिल्ली, 10 सितंबर 2025: लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, जो सीपीए भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, 11 सितंबर 2025 को बेंगलुरु स्थित विधान सौध में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है ÷विधानसभा के सदनों में वाद-विवाद और चर्चाएँ: जन विश्वास का निर्माण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति÷। विदेशी संसदों के पीठासीन अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अध्यक्ष और महासचिव को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है।

विधान सौध में आयोजित किए जा रहे उद्घाटन समारोह में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के सभापतियों/अध्यक्षों सहित पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे।

उद्घाटन सत्र के दौरान, कर्नाटक के मुख्य मंत्री, श्री सिद्धारमैया; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित विशिष्टजनों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष, श्री यू.टी. खादर फरीद स्वागत भाषण देंगे तथा सीपीए कर्नाटक शाखा के सचिव धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

कर्नाटक के राज्यपाल, श्री थावर चंद गहलोत और लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 13 दिसंबर 2025 को समापन सत्र को संबोधित देंगे।

इस तीन दिवसीय कार्यक्रम (11-13 सितंबर) का आयोजन सीपीए कर्नाटक शाखा के तत्वावधान में कर्नाटक विधान सभा द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री बिरला एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। सम्मेलन के दौरान, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, उप-पीठासीन अधिकारियों और सचिवों सहित प्रतिनिधि संसदीय महत्व के विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। पूर्ण सत्रों में विचारों का आदान-प्रदान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ ही भारत क्षेत्र में संसदीय संस्थाओं को मजबूत करने के बारे में चर्चा की जाएगी ।

कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के कार्यकर्ताओं ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए गए समुदायों के रहने के संबंध में गृह मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना और सीएए के खिलाफ गुवाहाटी, असम में धरना प्रदर्शन किया।

बिहार के पटना में परीक्षा तिथियों की घोषणा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) 4.0 के अभ्यर्थियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया।

ट्राई ने रेवाड़ी शहर (हरियाणा) में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का परीक्षण किया

पीआईबी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सामान्य दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए जुलाई-अगस्त 2025 के दौरान रेवाड़ी शहर (हरियाणा एलएसए में) में आयोजित इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के परिणाम जारी किए हैं। इस ड्राइव टेस्ट का उद्देश्य, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) की मोबाइल नेटवर्क सेवाओं (वॉयस और डेटा दोनों) की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन और सत्यापन करना है। आईडीटी के दौरान, ट्राई प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) जैसे कॉल सेटअप सफलता दर, डेटा डाउनलोड और अपलोड गति, आवाज की गुणवत्ता से जुड़े डेटा एकत्र करता है। इन्हें बाद में उपभोक्ताओं को सूचित करने और टीएसपी को अपनी सेवाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है।

ट्राई ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से, हरियाणा में 31-07-2025 से 02-08-2025 तक रेवाड़ी में 250.7 किलोमीटर की शहरी ड्राईव परीक्षण, 8 हॉटस्पॉट स्थानों और 1.1 किलोमीटर पैदल परीक्षण किए। ये परीक्षण जयपुर स्थित ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय की देखरेख में किए गए।

नीति आयोग ने (एमपीआई) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया

संवाददाता। नीति आयोग ने यूएनडीपी के सहयोग से 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसका उद्देश्य आउटरीच और राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करना है। इस कार्यशाला में भारत की एमपीआई यात्रा और एमपीआई की गणना के पीछे की तकनीकी पद्धति पर प्रकाश डाला गया।

नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला के हिस्से के रूप में 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आउटरीच और राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करना है।

इस सम्मेलन में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (यूएनडीपी, यूएनआरसीओ) और थिंक टैंक (आर्थिक विकास संस्थान, आईआईटी रुड़की, एनसीएईआर, सीईईडब्ल्यू, मानव विकास संस्थान और नज इंस्टीट्यूट) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के. बेरी की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र में ईएसी-पीएम के अध्यक्ष प्रो. एस. महेंद्र देव, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक श्री शोम्बी शार्प, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग, ओपीएचआई की निदेशक डॉ. सबीना अलकिरे और नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक श्री राजीब कुमार सेन ने कई विचारोत्तेजक संबोधन दिए। इस सत्र में गरीबी को कम करने, बेहतर शासन और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में एमपीआई के महत्व पर बल दिया गया।

एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया जिसमें राज्यों द्वारा सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन योजनाओं में लक्षित समूहों के लिए डेटा का उपयोग करने के तरीके और इन प्रयासों में एमपीआई को एकीकृत करने की क्षमता पर बात की गई। पैनल के सदस्यों ने कार्यक्रम के डिज़ाइन और वितरण में अधिक प्रभावी, डेटा-संचालित निर्णय लेने का समर्थन करने, जिसमें सर्वेक्षणों की समय-सीमा को कम करने मौजूदा डेटा को पूरक बनाना शामिल है, पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, उत्तर प्रदेश के संभव अभियान, आंध्र प्रदेश की शून्य गरीबी - पी4 और ओडिशा के सामाजिक सुरक्षा वितरण प्लेटफॉर्म जैसी विभिन्न पहलों को तैयार करने और लागू करने के अपने अनुभव भी साझा किए।

डिजिटल विकास और सस्ती आईसीटी हार्डवेयर उपलब्ध कराने के लिए एयर कंडीशनर, टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और पावर बैंक पर कम जीएसटी दर

पीआईबी

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में हाल ही में किए गए अगली पीढ़ी के सुधारों से इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत आने वाले क्षेत्रों, खासतौर पर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और आईसीटी हार्डवेयर (कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, स्विच, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्मार्टफोन और अन्य सभी संबंधित उपकरण) को बढ़ावा मिलेगा। दरों में कटौती से लोगों को सस्ती दर पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिलेंगे, साथ ही घरेलू विनिर्माण को मज़बूती मिलेगी, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम और स्टार्ट-अप्स को समर्थन मिलेगा, जिससे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा

एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन (एलसीडी और एलईडी) जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किये जाने से सस्ती दर पर वस्तु उपलब्ध होने से घरेलू मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे कंप्रेसर, डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर जैसे घटकों में मजबूत बैकवर्ड लिंकेज (उद्योग को अपने उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध) बनने की संभावना है, और प्लास्टिक, वायरिंग, कूलिंग सिस्टम, एलईडी पैनल और असेंबली सेवाओं से जुड़े एमएसएमई के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। ये सुधार स्थानीय विनिर्माण को भी बढ़ावा देंगे, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। डिशवॉशर पर जीएसटी में कटौती से घरेलू जीवन स्तर भी बेहतर होगा।

डिजिटल विकास और सस्ते आईसीटी हार्डवेयर की उपलब्धता

मॉनिटर और प्रोजेक्टर (गैर-टीवी) पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों और डिजिटल शिक्षण केंद्रों की व्यय लागत कम होगी। सस्ते आईसीटी हार्डवेयर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक संचायकों (गैर-लिथियम-आयन, पावर बैंक सहित) पर जीएसटी 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने से ऊर्जा भंडारण समाधान सस्ती दर पर उपलब्ध होंगे, डिजिटल उपकरणों के लिए बैकअप पावर में सुधार आएगा और घरों और कार्यस्थलों पर ऊर्जा कुशल प्रणालियों को अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

जीएसटी में कमी से आंतरिक सुरक्षा संचार ढांचा भी सुदृढ़ होगा। दो-तरफ़ा रेडियो (वॉकी-टॉकी) पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जिससे पुलिस, अर्धसैनिक बलों और रक्षा बलों की खरीद लागत कम आएगी।

नवीकरणीय ऊर्जा और संवहनीयता को बढ़ावा

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और सौर फोटोवोल्टिक सेलों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जिससे घरेलू और औद्योगिक, दोनों स्तरों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। कम्पोस्टिंग मशीनों पर भी अब 12 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिससे अपशिष्ट से ऊर्जा समाधानों और कम्पोस्टिंग तकनीकों को प्रोत्साहन मिलेगा और संधारणीय तथा स्मार्ट शहरों के निर्माण की परिकल्पना सुगमता से आगे बढ़ेगी।

जीएसटी सुधारों से भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलने की संभावना है। मांग को बढ़ावा मिलने तथा लागत मूल्य में कमी से घरेलू विनिर्माण तथा एमएसएमई के लिए अवसर उत्पन्न होंगे और रोज़गार सृजन होगा। इससे स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत का समेकन और गहरा होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद का आमसभा 11 सितंबर को

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद का वार्षिक आमसभा माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की अध्यक्षता में दिनांक 11 सितंबर 2025 गुरुवार को दोपहर 3 बजे से ÷ वीमतारा÷ स्वदेशी भवन के पास मधुपिले चौक शान्ति नगर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य विषय के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन 2024 - 25 , पूर्व वित्तीय वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट के साथ आगामी वर्ष हेतु अनुमानित बजट का अनुमोदन , चार्टर एकाउंटेंट की नियुक्ति, परिषद द्वारा संचालित बालगृह बालिका , बालगृह बालक , खुला आश्रय बालक माना कैम्प रायपुर, बालगृह बालिका कोंडागांव, वाणी वाचन श्रवण एवं बहु प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्र, दिव्यांग बच्चों का प्री प्रायमरी विशेष स्कूल शिक्षा का मन्दिर की गतिविधियो की जानकारी, आगामी योजनाओ के संबंध में चर्चा, पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यों का छत्तीसगढ़ सरकार के आयोग/निगम में नियुक्त होने पर उनका सम्मान किया जाएगा।

बिहान योजना ने बदल दी जिंदगी, खेत छुड़ाकर खड़ा किया कारोबार

गृहिणी से बनी सफल उद्यमी जानकी यादव की प्रेरणादायी यात्रा

पीएम आवास योजना के आवास निर्माण में सेंट्रिंग लगाकर कमा रही हैं मुनाफा

जांजगीर-चांपा / ग्राम पंचायत पिपरसत्ति की श्रीमती जानकी यादव, पहले एक साधारण गृहिणी थीं। घर की चौखट तक सीमित जीवन, चूल्हा-चौकी का काम और कभी-कभार मजदूरी से ही परिवार का गुजर-बसर चलता था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, यहाँ तक कि अपना खेत भी गिरवी रखना पड़ा। लेकिन वर्ष 2020 उनके जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। गाँव में बिहान टीम के आगमन से जानकी यादव श्री राधा रानी महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ते ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देने का निश्चय किया।

बिहान योजना के तहत जिले की महिलाएँ प्रधानमंत्री आवास निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। जानकी यादव जैसी सदस्य आज न केवल अपने परिवार को संवार रही हैं, बल्कि सामुदायिक विकास में भी योगदान दे रही हैं। सबसे पहले समूह को 60 हजार सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त हुआ, जिससे जानकी यादव ने अकेले ऋण लेकर छोटा कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। यह कदम उनके आत्मनिर्भर बनने की ओर पहला मजबूत प्रयास था। इसके बाद समूह के माध्यम से बैंक से ऋण सुविधा मिली। जानकी यादव ने 80 हजार का लोन लेकर सबसे पहले अपना गिरवी रखा खेत छुड़वाया। फिर सन 2024 में उन्होंने पुनः 60 हजार का ऋण लेकर सेंट्रिंग प्लेट्स एवं अन्य मकान निर्माण संबंधी उपकरण खरीदे और दूसरा आजीविका कार्य शुरू किया। आज उनका सेंट्रिंग व्यवसाय प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों लगाया जा रहा है जिससे उन्हें निरंतर अच्छी आमदनी हो रही है। आज जानकी यादव न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हैं, बल्कि अपनी बेटी को रायपुर में नर्सिंग की पढ़ाई भी करवा रही हैं। जानकी यादव कहती कि पहले मेरी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन बिहान योजना से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में उजाला आया। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपने परिवार को सम्मानजनक जीवन दे पा रही हूँ। गाँव की अन्य महिलाएँ भी इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

त्योहारी अवसरों पर दें ट्रेनों का ठहराव – विधायक कश्यप

जांजगीर-चांपा / विधायक ब्यास कश्यप ने नवरात्रि एवं दशहरा के अवसर पर जांजगीर-नैला रेलवे स्टेशन में सभी प्रमुख ट्रेनों की ठहराव के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि 22 सितंबर से 02 अक्टूबर तक नवरात्रि एवं दशहरा पर्व का आयोजन होगा। नवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष नैला में देवी दुर्गा का भव्य पंडाल लगता है। इसकी भव्यता एवं धार्मिक महत्व के कारण दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में नैला आते हैं। छत्तीसगढ़ ही नही वरन् मध्यप्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एवं महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नैला पहुंचते हैं। इससे जांजगीर-नैला रेलवे स्टेशन में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस अवधि में यदि प्रमुख ट्रेनों का ठहराव जांजगीर-नैला रेलवे स्टेशन में दिया जाता है, तो यात्रियों को तो सुविधा होगी ही, रेल प्रशासन को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। ब्यास कश्यप ने नवरात्रि एवं दशहरा के अवसर पर जांजगीर-नैला रेलवे स्टेशन में सभी प्रमुख रेल गाड़ियों के ठहराव की मांग की है। महाप्रबंधक रेलवे जोन बिलासपुर के द्वारा इस पर विचार कर शीघ्र उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है।

संतोष कुमार ठाकुर शिक्षक का निधन

राजनांदगांव।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धामनसरा के विज्ञान सहायक शिक्षक संतोष ठाकुर लगभग 45 वर्ष अल्पायु में निधन हो गया है। मानव सेवा के पुजारी के रूप बेलटिकरी का जन जन उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित किया जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख, जनपद सदस्य रोहित चंद्राकर, पूर्व जनपद सदस्य योगेंद्र दास वैष्णव,पूर्व सरपंच बेलटिकरी भूषण निषाद, पूर्व सरपंच धामनसरा पुनू राम पटेल, लोकेश गंगवीर,सरपंच डोडिया दिल्लू साहू, सरपंच पीतांबर कतलाम,सरपंच प्रतिनिधि धामनसरा कृतलाल पटेल, सरपंच प्रतिनिधि बुचीभरदा राहुल साहू, प्राचार्य अजय मसीह शिक्षक गण तथा क्षेत्र के आसपास के नागरिक बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए।

आपसी रंजीश पर घर अंदर घुसकर दो पक्षों मे मारपीट

दोनों पक्षों से छः आरोपीयों को पामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

जांजगीर चांपा /

आपसी रंजीश पर घर अंदर घुसकर दो पक्षों में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है जिसमें दोनों पक्षों से 6 आरोपीयों को पामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपीयों में पार्टी नम्बर 1से रामप्रसाद केंवट उम्र 43 वर्ष , संतोष केंवट उम्र 42 वर्ष , सोहित उर्फ रोहित केंवट उम्र 34 वर्ष सभी साकिनान मेकरी थाना पामगढ़ तथा पार्टी नम्बर 2 से पप्पू खरे उम्र 44 वर्ष , आदित्य खरे उम्र 24 वर्ष , समीर खरे उम्र 19 वर्ष सभी साकिनान मेकरी थाना पामगढ़ शामिल है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दोनो पक्ष से प्रार्थी आदित्य खरे एवं रघुराज केंवट साकिनान मेकरी थाना पामगढ़ द्वारा दिनांक 31 सितंबर 2025 को रात्रि मे थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराये थे कि रात्रि 9 एवं 9.30 बजे दोनो पक्ष के लोग घर अंदर घुसकर पूर्व रंजिश पर से आपस मे गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर राड, डण्डा एवं हाथ मुक्का से एक दूसरे पक्ष को मारपीट किये थे । इस पर दोनो पक्षो के व्यक्तियो को गंभीर चोट आयी थी जो दोनो पक्षो की रिपोर्ट पर थाना पामगढ मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना दौरान दोनो पक्षो को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया गया जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त राड, डण्डा को बरामद कर विधवित गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही मे उप पुलिस अधीक्षक विजय पैकरा (मुख्या.) जांजगीर निरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सउनि सरोज पाटले, रामदुलार साहू, प्रआर. अजय कंवर, आर. नवीन रात्रे, चंद्रशेखर कैवर्त, यशवंत पाटले का सराहनीय योगदान रहा।

जिले के 10 पीएम श्री विद्यालयों में मानदेय पर संगीत प्रशिक्षक एवं अंशकालीन योग प्रशिक्षण, खेल शिक्षक, प्रशिक्षकों हेतु आवेदन आमंत्रित

जांजगीर-चांपा / प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार जांजगीर-चांपा जिले के 10 पीएम श्री विद्यालयों (पीएमश्री शा.प्राथ.शा. कापन, शा. कन्या प्राथ.शा. बलौदा, शा.जन.प्राथ.शा. नवगवां, शा.प्राथ.शा. बरपाली चांपा, शा.प्राथ.शा. लखुर्री, शा.प्राथ.शा. मिसदा, शा.प्राथ.शा. भाठापारा नवागढ़, शा.प्राथ.शा. बारगांव, पीएमश्री स्कूल सेजेस क्र.-1 एवं पीएमश्री स्कूल सेजेस बलौदा) में मानदेय पर संगीत प्रशिक्षक एवं अंशकालीन योग प्रशिक्षण, खेल शिक्षक, प्रशिक्षकों हेतु आवेदन 22 सितम्बर 2025 सायं 5 बजे तक आमंत्रित किया गया है। जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा ने बताया कि संबंधित प्रशिक्षकों को प्रति माह 10 हजार रुपये एकमुश्त पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। योग, खेल शिक्षक, प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री अथवा योग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री निर्धारित की गई है, बी.पी.एड. डिग्रीधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार संगीत प्रशिक्षक हेतु संगीत में स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन 22 सितम्बर 2025 सायं 5 बजे तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) जिला मिशन समन्वयक, कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, जांजगीर-चांपा को रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं अन्य विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट httpsÑ//janjgir-champa.gov.in से प्राप्त की जा सकती है तथा जिला कार्यालय, समग्र शिक्षा एवं संबंधित पीएम श्री विद्यालयों से भी संपर्क किया जा सकता है।

बसईवाल परिवार के निज निवास राधा माधव ,वार्ड 05 में श्रीमद् भागवत कथा

श्रीमद्भागवत कथा महात्म्य के प्रवचन कर्ता राम लखन शास्त्री जी......

आयोजन दिनांक 8 सितंबर से 14 सितंबर तक ...

जांजगीर चांपा

वसाईवाल परिवार के निज निवास राधा माधव वार्ड नंबर 5 में 08 सितंबर 2025 दिन सोमवार को प्रातःकाल 9 बजें से तथा सायंकाल 5 ,00 बजें से 7:00 बजें तक कथा महात्म्य, आत्मदेव प्रसंग, महाभारत प्रसंग का रस प्रवाह हो रहा है, 8सितंबर सोमवार कपिल गीता,शिव चरित्र और भरत चरित्र, 9 सितंबर दिन मंगलवार को जड़ भरत चरित्र, अजामिल प्रसंग, प्रह्लाद चरित्र, नृसिंह अवतार, 10 सितम्बर बुधवार को गजेन्द्र मोक्ष, समुंद्र मंथन,वामन अवतार,श्रीराम कथा, श्रीकृष्ण प्राकट्य उत्सव होगा। 11सितंबर दिन गुरुवार को श्रीकृष्ण बाल लीला, मथुरा गमन,कंस वध, श्रीकृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव , 12 सितंबर दिन शुक्रवार को भगवान श्रीकृष्ण के अन्य विवाह ,राजसूय यज्ञ, सुदामा चरित्र तथा 13 सितंबर दिन शनिवार को उद्धव गीता , भगवान श्रीकृष्ण का स्वधाम गमन,14 सितंबर परिक्षित मोक्ष के साथ कथा महापुराण का समापन होगा ।

श्रीमद्भागवत एक धार्मिक और पवित्र अनुष्ठान.... रामलखन शास्त्री जी......

उन्होंने बताया कि धार्मिक आस्था रखने वाले श्रीमद्भागवत कथा महापुराण एक पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन हैं, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन कथा वाचक तथा जीवन प्रबन्धन राम लखन शास्त्री जी के मुखारविंद से अमृत शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर श्रद्धालु-जनों को बसईवाल परिवार द्वारा आमंत्रण-पत्र देना एक श्रेष्ठ विचार हैं । यह आयोजन श्रोताओं की आध्यात्मिक प्रवचन और उत्साह को बढ़ावा देगा । आयोजक बसई वाल परिवार ने श्रद्धालु-जनों को कथा महापुराण रसपान के लिए आमंत्रित किया हैं ।

शीघ्र मरम्मत निमार्ण न होने पर भी विधायक के साथ होगा आंदोलन

जांजगीर चांपा /

नैला से बलौदा सड़क मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर आज ब्लाक कांग्रेस कमेटी बलौदा ने विधायक के निर्देश पर आज कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है । ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त सड़क का शीघ्र मरम्मत या नवीन निर्माण होने की स्थिती में विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह के साथ बड़ी धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी ।

इस ज्ञापन के दौरान ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सदन यादव , कन्हैया राठौर महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी , खेमन शर्मा सरपंच जर्वे(ब) , राजा कश्यप पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत बलौदा , नवल किशोर सिंह सरपंच बुडगहन , दिनेश मिरी पूर्व सरपंच ढोरला, प्रितेश शुक्ला सरपंच महुदा बृहस्पत सिंह , मारकंडे साहू , रामनाथ पटेल , कन्हैयालाल , कविता डहरिया नगर पंचायत अध्यक्ष बलौदा , विक्रम सिंह गोड , पार्षद मनोज कश्यप , पंचराम रात्रे , दिलहरण दिवाकर पार्षद आदि कांग्रेसजन मौजूद रहे।

लोक अभियंता से मिल चूके विधायक - इस मसले को लेकर गत माह अकलतरा क्षेत्र के विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह लोक निर्माण विभाग के अभियंता से मिलकर क्षेत्र वासियों की पीड़ा से अवगत कराकर उक्त सड़क को जल्द से जल्द निमार्ण कराने की मांग के साथ कोयला की बड़ी बड़ी वाहनों की आवागमन की स्थिति से भी जिला प्रशासन को अवगत करा चूके हैं । जिला प्रशासन की निर्देश महज निर्देशों तक ही - इस मामले में अगर गौर किया जाए तो जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर जन्मेजय महोबे द्वारा आय दिन बैठकों के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिले में सड़कों की गढ्ढों का तत्काल मरम्मत किया जाए किंतु धरातल में यह निर्देश निर्देशों तक ही रह जाता है ।

कलिंगा विश्वविद्यालय ने लगातार चौथी बार एनआईआरएफ रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया

नया रायपुर, संवाददाता

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर ने लगातार चौथे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में विश्वविद्यालय कैटेगरी में 101-150 रैंक बैंड में स्थान हासिल करके एक बार फिर अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यह निरंतर प्रदर्शन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति विश्वविद्यालय के समर्पण को उजागर करता है। यह उल्लेखनीय है कि कलिंगा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो देश के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल है।

कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. संदीप गांधी ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पूरे स्टाफके अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनकी हार्दिक सराहना की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह लगातार रैंकिंग सामूहिक कड़ी मेहनत, नवीन शिक्षण विधियों, अनुसंधान और शिक्षा और समग्र विकास तथा शिक्षकों और छात्रों के प्रति विश्वविद्यालय के प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रमाण है।

भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय एनआईआरएफ रैंकिंग आयोजित करता है, जो शिक्षण, सीखने और संसाधनों, अनुसंधान और पेशेवर प्रथाओं, स्नातक परिणामों, आउटरीच और समावेशिता, और धारणा जैसे कई पहलुओं पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है। कलिंगा विश्वविद्यालय की शीर्ष 150 में निरंतर उपस्थिति इसकी मजबूत शैक्षणिक नींव, अनुसंधान उत्पादन और छात्र-केंद्रित पहल का प्रतिबिंब है।

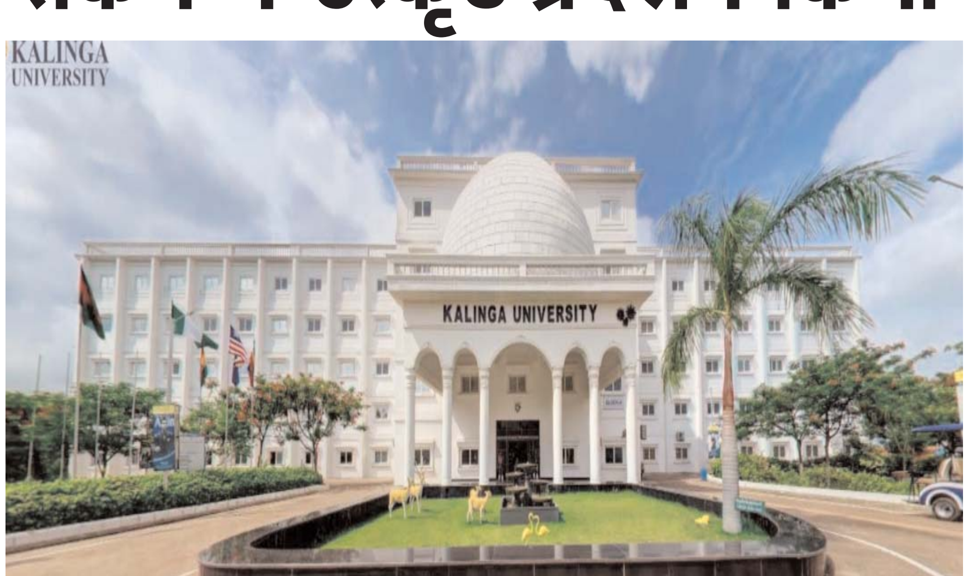

डॉ. गांधी ने शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता दोहराई तथा आने वाले वर्षों में रैंकिंग में और भी ऊपर आने का लक्ष्य रखा। इस मान्यता से कलिंग विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारी और छात्र शैक्षणिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित हुए हैं। यह उपलब्धि देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में से एक बनने की दिशा में कलिंगा विश्वविद्यालय की यात्रा में एक और मील का पत्थर है।

महिला कमांडो की टीम द्वारा शाम रात को गांव में निकाला जा रहा फ्लैग मार्च

अवैध शराब बिक्री नहीं करने, जुआ/सट्टा नहीं खिलाने संबंध में की जा रही है लोगो को जागरुक

जांजगीर चांपा / महिला कमांडो की टीम द्वारा पामगढ़ में फ्लैग मार्च निकालकर अवैध शराब व जुआ सट्टा के खिलाफ जन जागरूक किया है ।पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के असमाजिक तत्वों के व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा निरीक्षक मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में बीते दिनांक 9 सितंबर 2025 को पामगढ़ के महिला कमाण्डो का बैठक लिया लिया जाकर आवश्यक चर्चा किया गया एवं गांव में शांति व्यवस्था के लिए देर संध्या को पैदल फ्लैग मार्च किया । इस दौरान आवश्यक बिंदु पर चर्चा की गई जिसमें ग्राम में बाहरी व्यक्तियों के आवाजाही की सूचना देना , ग्राम में अवैध कारोबार में सम्मिलित व्यक्तियों की सूचना देना , गांव क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालो एवं जुआ सट्टा खेलने एवं खिलाने वालो के संबंध में जानकारी देना , ग्राम में साइबर/ट्रैफिक/ नशामुक्ति आदि के संबंध में ग्रामीणों को थाने के सहयोग से जागरूक करना शामिल है।

खास खबर

सतनामी समाज ने श्मशान भूमि की सुरक्षा एवं विकास को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कोरबा, ग्राम नोनबिर्रा के सतनामी समाज के लोगों ने श्मशान भूमि की सुरक्षा एवं विकास को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने बताया कि ग्राम की पारंपरिक श्मशान भूमि खसरा नंबर 581/1 व 582/2, रकबा 1 एकड़ 67 डिसमिल क्षेत्र में स्थित है, जिसे उनके पूर्वजों ने स्थापित किया था। यह स्थल समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि समय के साथ इस भूमि की उपेक्षा होती रही है। पंचायत स्तर पर इसे सुरक्षित करने की कोई ठोस पहल नहीं की गई है। वहीं आसपास के भूमि स्वामी इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते समाज के लोग अपने परंपरागत अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और उन्हें मानसिक, सामाजिक व शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मांग की कि श्मशान भूमि को सुरक्षित करने के लिए चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए तथा यहां मुक्तिधाम जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही इस भूमि को सार्वजनिक स्थल के रूप में संरक्षित कर समाजजनों को उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने का अवसर दिया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि श्मशान भूमि समाज की आस्था और परंपरा से जुड़ा स्थान है, इसलिए इसे अतिक्रमण से मुक्त कर स्थायी रूप से संरक्षित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। समाज ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगा, जिससे समाज के लोगों को शांति और सम्मान के साथ जीवनयापन का अवसर मिल सके।

चैपाल में युवक का महिलाओं पर विवादित दावा, गांव में मचा हड़कंप

कोरबा जिले के एक गांव में चैपाल की बैठक के दौरान अजीब स्थिति देखने को मिली। जानकारी के अनुसार, विकास उर्फ भोंकू नाम का एक युवक बैठक में पहुंचा और दो महिलाओं के साथ अपने विवाहोत्तर संबंध होने का दावा करने लगा। मामला कोरबी पुलिस चैकी क्षेत्र का है। युवकों द्वारा यह दावा करने से महिलाओं और उनके परिजनों में गहरी चिंता और नाराजगी उत्पन्न हो गई। परेशान ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना गांव के मुखिया को दी, जिसके बाद चैपाल में विशेष बैठक बुलाई गई।

एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल: आप ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने व बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग की

कोरबा,। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधिकारी और कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की मांगों को तत्काल पूरा करने तथा बर्खास्त किए गए 25 कर्मचारियों की बहाली की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार द्वारा 25 हड़ताली कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद 16 हजार से अधिक एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है।

छत्तीसगढ़ में ग्रिड पद्धति की खेती से रिटायरमेंट के बाद रची सफलता की नई कहानी

किसान रामरतन निकुंज ने की रिकॉर्ड पैदावार कर किसानों के लिए बनाया प्रेरणा का मार्ग

कोरबा संवाददाता।

छत्तीसगढ़ की धरती को हमेशा से अन्नदाता किसानों की कर्मभूमि कहा गया है। यहाँ की मिट्टी में परिश्रम, समर्पण और उम्मीद की सुगंध रची-बसी है। वर्षों से प्रदेश के किसान अपनी मेहनत और लगन से खेत खलिहानों को समृद्ध करते आए हैं। समय बदलने के साथ-साथ खेती-बाड़ी की पद्धतियाँ भी बदल रही हैं। परंपरागत खेती के साथ आधुनिक तकनीकों का संगम आज नए-नए चमत्कार कर रहा है।इन्हीं परिवर्तनों के बीच कोरबा जिले के झगरहा गाँव से एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी सामने आई जिन्होंने न केवल किसानों को, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दिया है, कि सफलता पाने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती, बल्कि सही सोच और मार्गदर्शन से असंभव सपने भी साकार किए जा सकते हैं।

यह कहानी है 67 वर्षीय प्रगतिशील किसान श्री रामरतन राम निकुंज की, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद खेती को अपनाया और अपनी मेहनत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो मुमकिन कर दिखाया जो बहुतों के लिए केवल कल्पना था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि इरादा पक्का हो और धरती माँ के प्रति लगाव सच्चा हो, तो खेत सुनहरी फसल से लहलहा उठते हैं और किसान समृद्धि की मिसाल बन जाते हैं।

'निजी परिचय और खेती की शुरुआत'

श्री रामरतन निकुंज पहले दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (ैम्ब्स) में फोरमेन इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2018 में नौकरी से निवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने गाँव में ही कृषि कार्य को अपनाने का निर्णय लिया। उनके पास कुल 5 एकड़ भूमि थी, जिसे उन्होंने नई सोच और नई तकनीक से खेती का मॉडल खेत बनाने की ठानी। 67 वर्ष की आयु में जहाँ अधिकांश लोग आराम करना पसंद करते हैं, वहीं श्री निकुंज ने खेती में अपनी नई पारी की शुरुआत की। उनका मानना है कि धरती माँ को अगर अपनापन दो, तो वह अनमोल धन धान्य लौटाती है।

विशिष्ट तरीका: वर्मी ग्रिड मैथड

शुरुआती वर्षों में किसान श्री निकुंज ने धान की कतार बोनी की पद्धति अपनाई। इसके बाद उन्होंने श्री विधि से धान की उपज प्राप्त की, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 2023 में उन्होंने वर्मी ग्रेड मेथड का प्रयोग शुरू किया, जिसने फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों में उल्लेखनीय सुधार किया। वर्मी ग्रिड मैथड, यह एक आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें जैविक खाद, विशेषकर वर्मी कम्पोस्ट (केचुआ खाद) का उपयोग कर खेत को कई खंडों में बाँटा जाता है। इस पद्धति में खेत की मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। खेत के अलग-अलग ग्रिड में वर्मी कम्पोस्ट डालने से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और पौधों को संतुलित पोषण मिलता है। समय-समय पर खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान ने कतारों में वीडर का उपयोग किया, जिससे न केवल खरपतवारों का प्रभावी नाश हुआ बल्कि खरपतवार नाशक और अन्य शारीरिक श्रम में भी महत्वपूर्ण बचत हुई। वर्मी ग्रिड मैथड के फायदे मिट्टी की उर्वरता वर्षों तक बनी रहती है, रासायनिक खाद व कीटनाशक पर निर्भरता कम हो जाती है, धान की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की लेंगे बैठक

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में होगी बैठक

कलेक्टर ने बैठक की तैयारी की समीक्षा कर दिए आवष्यक निर्देष

कोरबा लोकशक्ति।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा प्रवास पर रहेगें। मुख्यमंत्री श्री साय 10 सितंबरको प्रातः 11 बजे कलेक्टोरेट सभागार में आयोजितमध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के बैठक कीअध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ षासन के मंत्रीगण एवं प्राधिकरण के सदस्य शामिलहोंगे। जिला प्रशासन कोरबा द्वारा बैठक की गरिमामय आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां सुनिष्चित की जा रही है।

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकासप्राधिकरण के अंतर्गत कोरबा, गोरेला- पेंड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चैकी, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव,बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बालोद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कबीरधाम (कवर्धा), बिलासपुर, रायगढ़ एवं सक्ती जिला शामिल हैं। प्राधिकरण में 51सदस्य एवं 24 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। जो प्राधिकरणकी समीक्षा बैठक में शामिल होकर स्वीकृत कार्यो केसंदर्भ अपने विचार,सुझाव एवं शिकायत रखते हैं। **कलेक्टर ने तैयारियों के संबंध में ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश** कलेक्टर अजीत वसंत ने बैठक की गरिमामय आयोजन हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिष्चित करने के निर्देष दिए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर विषेष ध्यान देने हेतु अधिकारियों को निर्देषित किया। कलेक्टर ने बैठक में षामिल होने वाले व्हीव्हीआईपी, व्हीआईपी एवं अधिकारियों के ठहरने हेतु निर्धारित विश्राम गृहों का लाइजनिंग अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिष्चित करने की बात कही। कलेक्ट्रेट परिसर में लगाए जाने वाले विभागीय स्टॉलों के माध्यम से मुख्यमंत्री से भेंट होने वाले हितग्राहियों की भी जानकारी तैयार रखने के लिए कहा। उन्होंने आवष्यक स्थानों पर बेरिकेडिंग लगाने एवं बैठक व्यवस्था, विद्युत, पेयजल, पार्किंग सहित आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने एवं सभी अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने हेतु निर्देषित किया।

कलेक्टर श्री वसंत एवं पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी ने प्रषासनिक-पुलिस अधिकारियों के साथ प्राधिकरण बैठक की तैयारियों का जायजा लेते हुए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रवेश, बैठक कक्ष, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था आदि का अवलोकन किया। उन्होंने पेयजल, बेरिकेडिंग, विद्युत, रोड क्लियरेंस, एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान आयुक्त नगर निगम कोरबा श्री आषुतोष पाण्डेय, सीईओ जिला पंचायत श्री दिनेष नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेन्द्र पटेल सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

शिक्षक दिवस पर गुरुजनों का हुआ सम्मान, भव्य समारोह में उमड़ा आभार और श्रद्धा

कोरबा संवाददाता।

शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व छात्र परिषद् सरस्वती शिशु मंदिर प्रगतिनगर की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का कुशल संयोजन परिषद् अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री मनीष अग्रवाल ने किया।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री अजय अग्रवाल (प्रेसिडेंट, एम.बी. पावर, अनूपपुर) और श्री गुंजन शुक्ला (चीफ बायलर इंस्पेक्टर, छत्तीसगढ़ शासन) रहे। दोनों अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र के वास्तविक निर्माता हैं, जो अपने ज्ञान और संस्कारों से नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सुरेंद्र राठौर (अध्यक्ष, प्रबंध कार्यसमिति, विद्यालय) और श्री भरत राम साहू (व्यवस्थापक, प्रबंध कार्यसमिति) उपस्थित रहे। उन्होंने गुरुदृशिष्य परंपरा को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए शिक्षकों के योगदान को सर्वोपरि माना।

संयोजक श्री मनीष अग्रवाल ने कहा कि शिक्षक दिवस केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन की सफलता का आधार गुरुजनों का आशीर्वाद ही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पूर्व छात्र परिषद सदैव अपने शिक्षकों का सम्मान और विद्यालय परिवार से जुड़ाव बनाए रखेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य श्री लक्ष्मी नारायण जायसवाल ने की। उन्होंने शिक्षकों को बच्चों के मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प दोहराया।

इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संयोजक श्री विकास अग्रवाल, प्रांतीय चेयरमैन श्री अरुण केडिया, दर्री जमनीपाली शाखा के अध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री बालकिशन अग्रवाल, सदस्य श्री सुमित अग्रवाल सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे।

हाथियों का दल पहुंचा मोरगा, 17 ग्रामीणों के फसलों को किया तहस-नहस

कोरबा, संवाददाता।

कटघोरा वनमंडल के केंदई रेंज में सूरजपुर जिले से आए 12 हाथियों का दल बीती रात मदनपुर से आगे बढकर मोरगा क्षेत्र में पहुंच गया है जबकि 26 हाथी सफोदा बीट के सलईगोट गांव पहुंच गया है। 26 हाथियों के दल ने यहां पहुंचते ही भारी उत्पात मचाया और ग्रामीणों के खेतों में लगे धान की फसल को तहस-नहस कर दिया।

हाथियों के उत्पात से यहां के 17 ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। जिनकी फसल को हाथियों ने बुरी तरह चैपट कर दिया है। हाथियों के यहां आने तथा उत्पात मचाकर फसल को नुकसान पहुंचाए जाने की जानकारी आज सुबह तब लगी जब ग्रामीण अपने खेतों में फसल को देखने पहुंचे तो उसे तहस-नहस पाया। तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई जिस पर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचकर निगरानी में जुट गए हैं। 12 हाथियों के दल भी मोरगा पहुंचने से पहले रास्ते में कई किसानों के धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों द्वारा लगातार फसल रौंदे जाने से क्षेत्रवासी काफी हलाकान हैं। उधर एतमानगर रेंज के मड़ई क्षेत्र में भी 26 हाथियों की सक्रियता लगातार बनी हुई है। हाथियों का यह दल खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है।

ग्रामीणों ने पंचायत सचिव को हटाने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा

कोरबा, संवाददाता। ग्राम पंचायत रंगोले जनपद पंचायत पाली जिला कोरबा के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव सुनील कुमार कुर्रे के स्थानांतरण की मांग को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को ज्ञापन सौंपा।

ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सचिव सुनील कुमार कुर्रे पिछले 15 वर्षों से ग्राम पंचायत रंगोले में पदस्थ हैं, लेकिन वे पंचायत मुख्यालय से 15-20 किलोमीटर दूर पाली में निवास करते हैं। इस कारण वे पंचायत कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते। कभी-कभार कार्यालय आते भी हैं तो समय पर नहीं पहुंचते। उनकी इस लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये से पंचायत स्तर पर आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे आवास, पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और अन्य हितग्राही मूलक कार्य समय पर नहीं हो पाते। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे अपने कामों के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की कि पंचायत सचिव को फोन करने पर वे कभी कॉल रिसीव नहीं करते, जिससे आम जनता की समस्याएं और बढ़ जाती हैं।

ग्राम पंचायत रंगोले के निवासियों ने जिला पंचायत प्रशासन से मांग की है कि सचिव सुनील कुमार कुर्रे का शीघ्र स्थानांतरण कर दिया जाए और उनकी जगह एक कर्तव्यनिष्ठ व उत्तरदायी सचिव की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पंचायत कार्यों की पारदर्शिता और सुचारु रूप से संचालन हो सकेगा तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा।

ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी मांग को गंभीरता से लेकर शीघ्र कार्यवाही करेगा, ताकि पंचायत सचिव की मनमानी से हो रही परेशानियों का अंत हो सके और शासन की योजनाओं का लाभ समय पर उन्हें मिल पाए।

सड़क हादसा: दो बाइकों की भिड़ंत, एक युवक की मौत

कोरबा । जिले में एक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। रविवार सुबह पाली-चैतुरगढ़ मुख्य मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे में बाइक पर सवार तीन युवकों में से एक युवक अन्नू सिंह (पिता सहदेव, निवासी बनबांधा) की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भिजवा दिया अन्य दो युवकों के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर तेज रफ्तार और सावधानी की कमी आए दिन ऐसे हादसों का कारण बन रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. वि./यां. संभाग नवा रायपुर छ.ग.

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक. 1184 /NIT-14/2025–26/व.ले.लि. नवा रायपुर दिनांक 08/09/2025

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से निम्नालिखित मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

एन्आईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम/ No of Calls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
14 T0060	ऑडिटोरियम भवन बलौदा बाजार में अतिरिक्त स्टेज लाईटिंग का कार्य प्रथम आमंत्रण	6.88

नोट :-निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 22/09/2025 अपरान्ह 5:30 बजे तक है ।

निविदा संबंधी शर्ते विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है । इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है ।

शर्ते :- 1) उपरोक्त कार्यो के आबंटन प्राप्त होने पर ही नियामानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

G-252603350/1

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. वि./यां. संभाग नवा रायपुर छ.ग.

युक्तियुक्तकरण से योग्य शिक्षक सुदूर अंचलों में बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का पथ कर रहे प्रशस्त

- o विशेषज्ञ शिक्षक की नियुक्ति ने मांचाडोली विद्यालय के शैक्षिक परिवेश को दी नई दिशा, छात्रों में विषय की प्रति बढ़ी रुचि
- o शिक्षक श्री आर के चन्द्रा की प्रेरक शिक्षण शैली से
- o छात्र राजनीति विज्ञान से सामाजिक चेतना की ओर हो रहे अग्रसर'
- o राजनीति विज्ञान नहीं रहा सिर्फविषय, बना समाज की समझ का जरिया

कोरबा । कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक के घने वनांचल में बसा छोटा सा गांव मांचाडोली, जहां कभी शिक्षा के नाम पर सिर्फ बुनियादी ढांचा था, पर गुणवत्ता का गहरा अभाव था। यहां का हायर सेकेंडरी स्कूल वर्षों तक विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी से जूझता रहा।लालपुर, पाथा, कछार, बुल्लर साइड जैसे आसपास के गांवों से बच्चे पढ़ाई के लिए इसी स्कूल में आते हैं। परंतु दसवीं के बाद, जब संकाय चयन की बारी आती, तो अधिकांश विद्यार्थी सही मार्गदर्शन और विषय विशेषज्ञ न होने की वजह से अपनी रुचि के विपरीत विषय चुनने को मजबूर होते। कला संकाय में शिक्षक के अभाव में कई बच्चों को मनचाहा विषय त्याग कर अन्य संकाय चुनना पड़ता था जिससे छात्रों के लिए पढ़ाई बोझ बन जाती थी, और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता था।

युक्तियुक्त करण प्रक्रिया से आया बदलाव का दौर:-

राज्य सरकार की शिक्षकों की युक्तियुक्त करण प्रक्रिया के अंतर्गत मांचाडोली के हायर सेकंडरी स्कूल में कला, गणित, विज्ञान व अन्य विषयों के योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षको की पदस्थापना हुई हैं। प्रकिया के तहत मांचाडोली में राजनीति विज्ञान विषय के लिए श्री आर. के. चन्द्रा जैसे विशेषज्ञ शिक्षक की नियुक्ति ने विद्यालय के शैक्षिक परिवेश को नई दिशा दी है। शिक्षक चन्द्रा ने विषय को सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन और समाज से जोड़ते हुए पढ़ाना शुरू किया।पूर्व में विद्यालय में राजनीति विज्ञान जैसे जटिल विषय में बच्चों की समझ कमजोर थी, रुचि कम होने से छात्र विषय को समझने के बजाय रटा मारकर याद करने की कोशिश करते थे जिससे कक्षा का परिणाम भी औसत ही रहते थे।

शिक्षक श्री चन्द्रा ने आते ही कक्षा में पढ़ाई के तरीके को बदला। किताबों से आगे बढ़कर उन्होंने राजनीति विज्ञान को जीवन से जोड़ दिया। उनकी गहराईपूर्ण विषय-ज्ञान और व्यावहारिक शिक्षण शैली ने छात्रों को विषय की जटिलताओं से उबारकर एक नई सोच और समझ की ओर अग्रसर किया है। अब छात्र राजनीति विज्ञान को सिर्फ एक पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि समाज, शासन और नागरिक जिम्मेदारी के रूप में देखने लगे हैं।कक्षा 12वीं कला संकाय की संजना यादव, साक्षी चैहान, युवराज यादव, आयुष जगत, लक्ष्मी नारायण केवर्त सहित अन्य छात्रों में अब विषय को लेकर रुचि और आत्मविश्वास बढ़ा है।बच्चों में विषय के प्रति जो रुचि, उत्साह और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति देखने को मिली है, वह पहले नहीं थी।

विविध पौराणिक प्रसंगों एवं आधुनिक घटनाओं पर आधारित सुसज्जित झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र : झांकियों को देखने रायपुर में उमड़ा जनसैलाब

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 8 सितंबर की देर रात राजधानी रायपुर के हृदयस्थल जयस्तंभ चौक स्थित नगर निगम द्वारा निर्मित स्वागत मंच पर पहुंचे और ऐतिहासिक गणेश विसर्जन यात्रा में शामिल होकर झांकियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रायपुर की गणेश विसर्जन झांकी अत्यंत ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश से छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐतिहासिक विसर्जन यात्रा में आमंत्रित करने के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया।उल्लेखनीय है कि विगत दिवस राजधानी रायपुर में शाम 8 बजे से ही गणेश झांकी यात्रा प्रारंभ हो गई थी। इस बार भी निर्धारित रूट पर शारदा चौक से झांकियों को टोकन प्रदान किया गया। झांकियां तेलघानी नाका, राठौर चौक और तात्यापारा से होकर शारदा चौक में एकत्रित हुईं, तत्पश्चात एक-एक कर आगे बढ़ीं। ये सभी झांकियां जयस्तंभ चौक से होते हुए मालवीय रोड, सदर बाजार, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती, लाखेनगर, अश्वनी नगर, सुंदर नगर और रायपुरा मार्ग से होकर महादेव घाट तक पहुंचीं। इस वर्ष भी झांकियों को विभिन्न विषयों पर आकर्षक रूप से सजाया गया। इनमें विविध पौराणिक प्रसंगों के साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर और राफेल विमान की झलक भी देखने को मिली। रायपुर की सड़कों पर झांकी के रूप में राफेल विमान का दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

सीईओ जिला पंचायत ने आरंग में किया शासकीय कार्यों का निरीक्षण

रायपुर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर आज जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन ने आज आरंग विकासखंड के विभिन्न शासकीय कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत कुकरा में कैनाल मरम्मत कार्य की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टूटे हुए कैनाल की शीघ्र मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग और अनुविभागीय अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके बाद श्री बिश्वरंजन ने ग्राम रीवा स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम में 'दीक्षा ऐप' के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, सेवानिवृत्त शिक्षकों से शैक्षणिक सहयोग का आग्रह करने को भी कहा। साथ ही, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम रीवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किया और भवन जीर्णोद्धार कार्य की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने संबंधित अभियंता और प्रभारी अधिकारी को कार्य को निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जनपद पंचायत आरंग के सीईओ श्री अभिषेक बनर्जी, जनपद सदस्य श्रीमती कृष्णा महेश साहू सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उपसरपंच महेंद्र बघेल रहस्यमय ढंग से लापता

सक्ती, । छत्तीसगढ़ के सक्ती ज़िले के ग्राम पंचायत करही के उपसरपंच महेंद्र बघेल अचानक लापता हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, वे 6 सितंबर की रात करीब 10 बजे से गायब हैं और अब तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने उन्हें आसपास के क्षेत्रों में तलाशा और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। थक-हारकर परिजन 7 सितंबर को बिर्रा थाना पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और 6 से 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि 36 घंटे बीत जाने के बाद भी महेंद्र बघेल का कोई सुराग नहीं मिला है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गहरी चिंता और आशंका है। कुछ लोगों ने अनहोनी की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है और लापता उपसरपंच की तलाश लगातार जारी है।

नवाटोला गांव में महिला के घर से 5 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार

0 छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के चांदनी थाना क्षेत्र के नवाटोला गांव में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ रखने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया

सूरजपुर, 08 सितंबर (आरएनएस)। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव की एक महिला अपने घर में गांजा छिपाकर रखी है। सूचना मिलते ही चांदनी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के घर छापा मारा। छापेमारी के दौरान सफेद बोरे में पैक किए गए छह पैकेट गांजा बरामद हुए। इनमें से चार पैकेट एक-एक किलो के थे, जबकि दो पैकेट आधा-आधा किलो के। कुल बरामद गांजे का वजन 5 किलो और अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 50 हजार रुपये बताया जा रहा है। पुलिस ने महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ङ) के तहत केस दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। चांदनी थाना पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे मादक पदार्थों या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

कुटरू फरसेगाढ़ अधूरे मार्ग को प्रारंभ करवाने विधायक विक्रम मण्डावी ने कलेक्टर से मुलाक़ात कर की चर्चा

बीजापुर, क्षेत्रीय विधायक विक्रम मण्डावी ने कुटरू फ़रसेगढ़ मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को तत्काल प्रारम्भ करते हुए पूर्ण करवाने के संबंध में कलेक्टर संबित मिश्रा से विस्तृत चर्चा कर मांग पत्र सौंपा। वर्ष 2021-22 में स्वीकृत कुटरू फ़रसेगढ़ मार्ग पर लगभग 12.60 किलोमीटर सड़क की चौड़ीकरण, डामरीकरण सहित पुल पुलियों का निर्माण होना शेष है। सड़क अधूरी होने के कारण क्षेत्रवासियों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों की परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय विधायक विक्रम मण्डावी ने जिला कलेक्टर संबित मिश्रा से सड़क निर्माण के कार्य को तत्काल प्रारम्भ करने के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए एक मांग पत्र भी सौंपा।

वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णुदेव

छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता

तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या दोगुनी, 17 से बढ़कर हुई 35

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक सम्पन्न

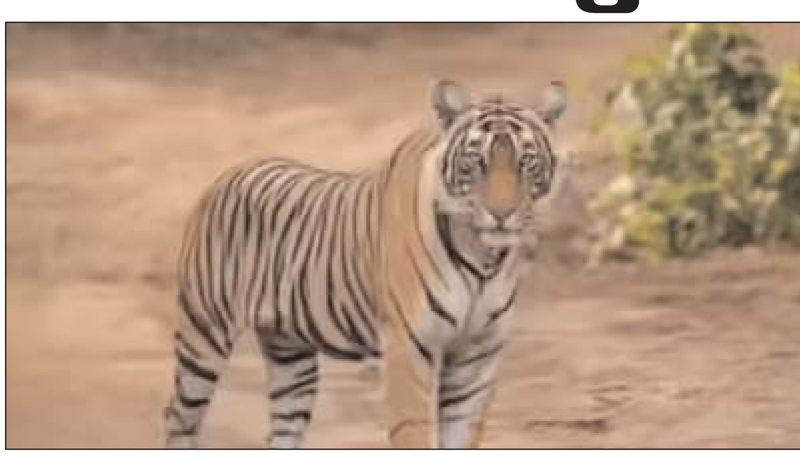

रायपुर छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या पिछले तीन वर्षों में दोगुनी हो गई है। वर्ष 2022 में जहां बाघों की संख्या 17 थी, वहीं अप्रैल 2025 के सर्वेक्षण में यह बढ़कर 35 हो गई। यह जानकारी आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सम्पन्न छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक में दी गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता है। हमारा राज्य वन संपदा और वन्य प्राणियों के मामले में अत्यंत समृद्ध है। इन्हें सुरक्षित और विकसित करने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में बाघों की संख्या में तीन वर्षों के भीतर हुई दोगुनी वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बाघों की संख्या 17 से बढ़कर 35 होना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में संतोषजनक कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हमें अन्य वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी ठोस प्रयास करने होंगे। छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जशपुर जिले के नीमगांव में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहां प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु आवश्यक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों की पहचान कर उनका भी विकास किया जाना चाहिए। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य में बाघों की संख्या के साथ-साथ अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन में भी वृद्धि हुई है तथा उनके रहवासों में सुधार के प्रयास जारी हैं। आगे इसके और बेहतर परिणाम जनता के सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि आज पारित प्रस्ताव जनहित के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो शांति का वातावरण स्थापित करने में सहायक होंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वन्यजीवों एवं जैव विविधता को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।बोर्ड के सदस्य सचिव श्री अरुण कुमार पांडेय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा विभागीय उपलब्धियों और एजेण्डा पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य में सर्वाधिक बाघ अचानकमार टाइगर रिज़र्व में हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड की 14वीं बैठक में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व में मध्यप्रदेश से बाघ एवं बाघिन के ट्रांसलोकेशन की अनुमति मिल चुकी है। शीघ्र ही ट्रांसलोकेशन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजकीय पशु वनभैंसा की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। असम से लाए गए वनभैंसों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण हेतु भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ÷मैना मित्र÷ नामक समूह का गठन किया गया है, जो मैना के संरक्षण और उनके रहवास की निगरानी करता है। टाइगर रिज़र्व और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अन्य सुविधाएं विस्तारित की जा रही हैं, जिससे समीपवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा और वन्यजीव संरक्षण में भी सहयोग प्राप्त होगा।

प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां के तहत शासकीय कर्मचारियों ने अपने जन्मदिन पर बच्चों के संग साझा की खुशियां

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित अभिनव पहल प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां के तहत रायपुर जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी अब अपने जन्मदिवस को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए नन्हें बच्चों संग खुशियां बांट रहे हैं। इसी कड़ी में लेक्चरर श्री भीखम राम साहू तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुपरवाइजर श्री उभय राम साहू ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आंगनबाड़ी तथा स्कूली बच्चों के साथ विशेष समय बिताया। दोनों अधिकारियों ने बच्चों के साथ केक काटा तथा उन्हें फल, मिठाई, पौष्टिक आहार वितरित की। इस पहल के तहत कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह द्वारा जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एसएमएस और ई-कार्ड के माध्यम से शुभकामनाएं भेजी जाती हैं और उन्हें पास के आंगनबाड़ी या विद्यालय में बच्चों संग जन्मदिन मनाने हेतु प्रेरित किया जाता है।अपने अनुभव साझा करते हुए दोनों कर्मचारियों ने कहा, बच्चों के साथ जन्मदिन मनाना हमारे लिए अत्यंत सुखद अनुभव रहा। समाज से जुड़कर अपनी खुशियां बांटना एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है।

पंजीयन कराए, निःशुल्क यात्रा कर डोंगरगढ़ दर्शन करें

रायपुर (संवाददाता)।

जगत जननी मां दुर्गा के पावन पर्व शारदीय नवरात्र का शुभारंभ सोमवार, 22 सितंबर से हो रहा है. मां काली सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष की तरह निःशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन-10 का शुभारंभ 22 सितंबर से किया जाएगा. समिति के अध्यक्ष दीपक भारद्वाज (पोल्ले) ने बताया, इस यात्रा के लिए पूर्व पंजीयन अनिवार्य रखा गया है. वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर सीटें आबंटित की जाएंगी. पूर्व पंजीयन के लिए समिति के इंदिरा चौक, श्यामनगर स्थित कार्यालय में 17 से 20 सितंबर तक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे एवं शाम 4 से 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है. टिकट आरक्षण 'पहले आओ, पहले पाओ' की तर्ज पर किया जाएगा।

यह निःशुल्क यात्रा इस वर्ष भी 4 बसों के माध्यम से कराई जाएगी. ये बसें क्रमशः एक-दूसरे के पीछे डोंगरगढ़ पहुंचेगी. जो प्रातः 09.30 बजे प्रस्थान स्थल से छूटेंगी व गंतव्य स्थल पहुंचकर और श्रद्धालुओं के दर्शन करने के बाद निर्धारित समय पर डोंगरगढ़ से वापस रायपुर लौटेंगी. यह यात्रा 22 से 26 सितंबर तक अर्थात् पांच दिनों तक चलेगी. यदि औसतन 60 यात्री 1 बस में सुविधाजनक रूप से यात्रा करते हैं, तो रोजाना 240 यात्री एक दिन में यात्रा कर सकेंगे.

जीएसटी में बदलाव से राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति

जीएसटी में बदलाव से राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति, कारोबारियों और आमजन को मिलेगा लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में राज्य के विभिन्न व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधियों ने भेंट कर जीएसटी में किए गए सुधारों के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जीएसटी ने न केवल व्यापार जगत को सशक्त किया है, बल्कि पारदर्शिता और कर संग्रहण में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था भारत को वैश्विक व्यापार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की कर व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माने जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राज्य और देश के व्यापार जगत को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जीएसटी में किए गए हालिया सुधारों से राज्य के उद्योगों और व्यापारियों के साथ-साथ आमजन को भी महत्वपूर्ण राहत मिली है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। यह सुधार भविष्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित राज्य के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

क्या इस सिस्टम में करप्शन भी स्कैन हो जाएगा?, बकावंड विकासखंड की सभी ग्राम पंचायतों में कार्यों का डिजिटलीकरण

क्यूआर कोड स्कैनर से मिलेगी पूरी जानकारी, भ्रष्टाचार का भी ब्यौरा मिल जाए तो बात बने

बकावंड। छत्तीसगढ़ और संभवतः पूरे में पहली बार किसी विकासखंड में सारे कार्यों की जानकारी क्यूआर कोड को स्कैन करते ही सेलफोन पर आ जाएगी। यह सौभाग्य मिला है बस्तर जिले के विकासखंड बकावंड को। इस ब्लॉक की सभी 93 ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड सुविधा शुरू हो गई है। बस्तर जिला प्रशासन की यह पहल निसंदेह सराहनीय है, मगर यदि क्यूआर कोड स्कैन करते ही कार्यों में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, यह जानकारी भी मिल जाए तो कोई बात बने। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की मनरेगा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड में इस योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए नई पहल की जा रही है। विकासखंड की सभी 93 पंचायतों में क्यूआर कोड आधारित नई प्रणाली शुरू की गई है। इसके जरिए ग्रामीण अपने गांव में पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। स्मार्टफोन से क्यूआर कोड स्कैन करते ही कार्य का विवरण, व्यय और प्रगति जैसी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। बकावंड विकासखंड में मनरेगा के लिए यह पहल केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया और राज्य सरकार की पारदर्शिता की नीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना और योजनाओं की निगरानी का अधिकार देना है। अब ग्रामीणों को जानकारी के लिए न तो पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही अधूरी सूचनाओं पर निर्भर रहना होगा। सितंबर से बकावंड विकासखंड की सभी ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। यह प्रणाली न केवल समय और श्रम की बचत करेगी, बल्कि ग्रामीणों को तकनीकी रूप से सशक्त भी बनाएगी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन 11 को बस्तर में

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार 11 सितंबर 2025 को बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के विकास को गति देना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा यह पहल की जा रही है। इससे पहले भी इस तरह के आयोजन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, टोक्यो, ओसाका और सियोल में हो चुके हैं, जिनसे नवंबर 2024 से अब तक 6.65 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। **प्रमुख विशेषताएं और नीतिगत पहल :** यह आयोजन छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत, 1000 करोड़ से अधिक का निवेश या 1000 से अधिक रोजगार सृजित करने वाली परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। नीति में पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे बस्तर में होटल, इको-टूरिज्म, और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी परियोजनाओं पर 45त्न तक सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, बस्तर के 88त्न ब्लॉक ग्रुप-3 श्रेणी में आते हैं, जिससे निवेशकों को अधिकतम लाभ मिल सकेगा।

समावेशी विकास के लिए विशेष प्रावधान : नीति में समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया हैः एससी/एसटी उद्यमियोंः 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है। नक्सलवाद प्रभावित परिवार : इन परिवारों के व्यक्तियों को 10त्न अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। आत्मसमर्पित नक्सलीः औद्योगिक इकाइयों में रोजगार देने पर 5 साल तक उनके वेतन पर 40 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 5 लाख प्रति वर्ष) दी जाएगी।

इसके अलावा, बस्तर में स्टील सेक्टर की इकाइयों को 15 साल तक रॉयल्टी रीइम्बर्समेंट की सुविधा मिलेगी।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। **संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।**
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily **कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल** (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)